सांध्य दैनिक
नई दृष्टिबिंदु
सच की शक्ति, जनता की दृष्टि
PRGI Reg No - CTHIN/25/A3746

सु-विचार

" बाहर की चुनौतियों से नहीं, हम अपनी अंदर की कमजोरियों से हारते हैं...!"

अज्ञात...

वर्ष–01 अंक–87 | संपादक आलोक तिवारी | दुर्ग, शुक्रवार 17 अप्रैल 2026 | पृष्ठ 08 | मूल्य –2 रुपए

नड्डा के नाम पर 'धंधा' ! फर्जी जांच का खेल, सिस्टम बना मोहरा

विशेष संवाददाता / भिलाई

भिलाई में एक ऐसा चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसने न सिर्फ स्वास्थ्य व्यवस्था की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं, बल्कि यह भी दिखा दिया है कि कैसे एक कथित पत्रकार ने केंद्रीय मंत्री के नाम का इस्तेमाल कर पूरे सिस्टम को अपने इशारों पर नचाने की कोशिश की।

मामला कथित पत्रकार गुरमीत सिंह वाधवा से जुड़ा है, जिस पर अब ब्लैकमेलिंग और उगाही का गंभीर आरोप लगा है। हैरानी की बात यह है कि जिस व्यक्ति के खिलाफ शिकायत दर्ज हुई है, उसी के एक पत्र के आधार पर छत्तीसगढ़ का स्वास्थ्य विभाग हरकत में आ गया और अस्पतालों की जांच तक करा डाली।

जांच के नाम पर उगाही का आरोप

इसी बीच एसबीएस अस्पताल प्रबंधन ने 15 अप्रैल को एक FIR दर्ज कराई, जिसमें आरोप लगाया गया कि गुरमीत सिंह वाधवा ने अस्पताल से पांच लाख रुपये की मांग की थी। रकम नहीं देने पर उसने RTI लगाने और बदनाम करने की धमकी दी।

FIR के मुताबिक, आरोपी पहले अस्पताल में इलाज के दौरान मुफ्त में दिए गए इंजेक्शन का बिल मांगता रहा, और बाद में उसी बिल को फर्जी बताकर दबाव बनाने लगा। आरोप है कि उसने अस्पताल प्रबंधन के चेंबर में घुसकर अभद्रता भी की।

फर्जी पहचान और संदिग्ध नेटवर्क

वाधवा ने अपने पत्र में खुद को फोर्ब्स इंटरनेशनल नामक मैगजीन का मैनेजिंग एडिटर बताया था। लेकिन जांच में सामने आया कि पत्र में दिए गए पांच में से चार फोन नंबर बंद थे, जबकि एक नंबर किसी महिला का निजी नंबर निकला। इससे पूरे नेटवर्क की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।

सबसे बड़ा सवाल–सिस्टम इतना संवेदनशील क्यों?

इस पूरे घटनाक्रम ने कई असहज सवाल खड़े कर दिए हैं—क्या किसी भी व्यक्ति के दावे पर स्वास्थ्य विभाग इतनी जल्दी सक्रिय हो जाता है? क्या केंद्रीय मंत्री के नाम का हवाला देना ही जांच के लिए पर्याप्त आधार बन गया? और सबसे अहम—क्या यह सिर्फ एक व्यक्ति का खेल है या इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है?

सिस्टम की तत्परता या लापरवाही?

जिस तेजी से विभाग ने एक संदिग्ध पत्र पर कार्रवाई की, वह अब खुद विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ऊपर से दबाव का डर दिखाकर सिस्टम को इस्तेमाल किया जा रहा है? फिलहाल पुलिस और प्रशासन जांच में जुटे हैं, लेकिन यह प्रकरण साफ संकेत दे रहा है कि अगर समय रहते ऐसे फर्जी प्रभाव पर लगाम नहीं लगाई गई, तो सिस्टम को गुमराह कर बड़े स्तर पर खेल खेले जा सकते हैं।

पत्र में पावर, हकीकत में फर्जी खेल

बताया जा रहा है कि 28 नवंबर 2025 को गुरमीत सिंह वाधवा ने राज्य के मुख्य सचिव को एक पत्र लिखा, जिसमें उसने दावा किया कि उसे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे.पी. नड्डा द्वारा छत्तीसगढ़ के हर जिले में पांच–पांच अस्पतालों की जांच का जिम्मा सौंपा गया है। पत्र में उसने भिलाई के एसबीएस अस्पताल की जांच कर कई खामियां होने का आरोप भी लगाया।

लेकिन जब इस पत्र के आधार पर स्वास्थ्य विभाग ने जांच कराई, तो सारी कहानी उलटी निकल गई। सीएमएचओ दुर्ग द्वारा गठित टीम ने स्पष्ट किया कि अस्पताल में सभी सुविधाएं मानकों के अनुरूप हैं और वाधवा द्वारा लगाए गए आरोप पूरी तरह निराधार हैं। इसके बाद पूरे मामले को क्लीन चिट देते हुए बंद कर दिया गया।

शेड में लगी आग, कारें जलकर हुई खाक

नई दृष्टिबिंदु / भिलाई

हुडको स्थित पानी टंकी के पास अनाधिकृत रूप से खाली भूमि पर कब्जा कर बनाए गए लगभग तीन से चार शेड में गुरुवार की शाम पांच बजे जोरदार आग की लपटे उठती दिखी। जिससे सभी क्षेत्रवासी दहशत में आ गये। शेड के अंदर खड़ी कारे पुरी तरह जल गई और कुछ शेड मे एलपीजी सिलेंडर भी रखे मिले लेकिन किसी प्रकार की जान की कोई हानी नही हुई है। आग लगने का कारण शेड के पिछे स्थित झाड़ियों मे कचरा जलाने की नियत से किसी ने दोपहर में आग लगा दी थी जिसकी आंच फैलते–फैलते शेड तक पहुंची और शेड मे रखे समान कार बाइक को अपनी चपेट में ले लिया।

वार्ड पार्षद एंव महापौर परिषद के सदस्य सीजू एंथोनी ने तत्काल मौके पर पंहुच कर फायर ब्रिगेड को बुलाया और स्थिति को संभाला एल पी जी सिलेंडर को तुरंत हटाया गया नही तो गंभीर हादसा हो सकता था।

महिला आरक्षण कानून लागू : अधिसूचना जारी होने के बाद बोले पीएम मोदी– नारी शक्ति मजबूत भारत की पहचान

नई दृष्टिबिंदु / नईदिल्ली

देश में महिला आरक्षण कानून 2023 लागू हो गया है। केंद्र सरकार ने इसके लिए अधिसूचना भी जारी कर दी है। इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को देश की नारी शक्ति की जमकर सराहना की और मातृशक्ति को एक मजबूत भारत की पहचान बताया।

वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर अपने पोस्ट की श्रृंखला, सुभाषितम में लिखा– हमारी नारी शक्ति सशक्त भारत की पहचान है। देश की माताएं–बहनें और बेटियां अपनी अटूट संकल्पशक्ति, निष्ठा और सेवाभाव से आज हर क्षेत्र में भारतवर्ष का गौरव बढ़ा रही हैं। इसके साथ ही पीएम मोदी ने संस्कृत के दो श्लोक भी लिखे हैं।

अब यह कानून 16 अप्रैल 2026 से प्रभावी हो गया है। इस कानून के तहत लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित रहेंगी। संसद ने सितंबर 2023 में 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' को मंजूरी दी थी। इसे महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।

हालांकि, 2023 के इस कानून के अनुसार आरक्षण का फायदा 2029 से पहले नहीं मिल सकेगा, क्योंकि इसे 2027 की जनगणना के बाद होने वाली परिसीमन प्रक्रिया से जोड़ा गया है। वर्तमान में लोकसभा में जिन तीन विधेयकों पर चर्चा चल रही है, उनका उद्देश्य महिला आरक्षण को 2029 से लागू करना है। अधिकारियों के मुताबिक, कानून लागू हो जाने के बावजूद मौजूदा लोकसभा में यह आरक्षण लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसके लिए अगली जनगणना के आधार पर परिसीमन प्रक्रिया पूरी होना जरूरी है।

संसद में अभी इससे जुड़े तीन अहम विधेयकों पर चर्चा चल रही है। इनमें लोकसभा की कुल सीटें बढ़ाकर 850 करने का प्रस्ताव भी शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी ने सदन में भरोसा दिया कि परिसीमन के दौरान किसी भी राज्य के साथ भेदभाव नहीं होगा। उन्होंने इसे 'मोदी की गारंटी' बताया और कहा कि यह नारी शक्ति का हक है। गृहमंत्री अमित शाह ने भी साफ किया कि दक्षिण के राज्यों की सीटें कम नहीं होंगी। उन्होंने आंकड़े देते हुए बताया कि दक्षिण भारत की सीटें 129 से बढ़कर 195 हो जाएंगी। अकेले तमिलनाडु की सीटें 39 से बढ़कर 59 होने की उम्मीद है।

विधेयक पेश करने हुई वोटिंग

लोकसभा में संविधान (131वां संशोधन) विधेयक 2026 को पेश करने के प्रस्ताव पर मतदान हुआ, जिसमें अधिकतर सांसदों ने है। सरकार के पक्ष में वोट दिया। विधेयक के पक्ष में 251 वोट और विरोध में 185 वोट पड़े। विपक्षी सांसदों ने इस विधेयक को पेश करने के फैसले के खिलाफ मतविभाजन (वोटिंग) की मांग की थी, लेकिन वोटिंग में सरकार का पलड़ा भारी रहा।

850 सांसद होंगे

संशोधन बिल में लोकसभा सांसदों की संख्या 850 करने का प्रस्ताव मौजूदा संख्या 543 है। राज्यों में 815 और केंद्र शासित प्रदेशों में 35 तक सीटें होगी। सीटों की सटीक संख्या तय करने के लिए परिसीमन भी किया जाएगा। 273 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी।

गृहमंत्री शाह ने कहा– धर्म के धार पर नहीं होगा आरक्षण

लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष के नेताओं के बयानों पर जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा। दरअसल अखिलेश यादव ने मुस्लिम महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण की मांग की। इस पर शाह ने कहा समाजवादी पार्टी सभी टिकट मुस्लिम महिलाओं को दे दें तो हमें क्या आपत्ति होगी। वहीं अखिलेश यादव ने जनगणना को लेकर भी सवाल उठाया था।

वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल सहित 19 लोगों के खिलाफ हुआ अपराध दर्ज

पीएमओ ने की मुआवजे की घोषणा, मृतक के परिजन को 35–35 लाख और नौकरी देगी कंपनी

नई दृष्टिबिंदु / सक्ती

छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले में हुए भीषण वेदांता पावर प्लांट हादसे ने अब कानूनी मोड़ ले लिया है। प्रारंभिक जांच में प्लांट प्रबंधन की गंभीर लापरवाही सामने आने के बाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल, प्लांट हेड देवेंद्र पटेल सहित कुल 19 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी है। सभी आरोपियों पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 106, 289 और 3–5 के तहत मामला कायम किया गया है।

यह कार्रवाई उस दर्दनाक हादसे के बाद हुई है, जिसने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया। 14 अप्रैल को वेदांता पावर प्लांट में बॉयलर ब्लास्ट के चलते अब तक 20 मजदूरों की मौत हो चुकी है, जबकि 16 घायल अलग–अलग अस्पतालों में जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं।

लापरवाही की कीमत मजदूरों की जान

प्रशासन द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, मृतकों में 5 छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी हैं, जबकि 15 मजदूर अन्य राज्यों से आए थे। हादसे के बाद सामने आए तथ्यों ने साफ संकेत दिए हैं कि सुरक्षा मानकों की अनदेखी इस त्रासदी की बड़ी वजह हो सकती है।

अब बड़ा सवाल– जिम्मेदार कौन?

इतने बड़े औद्योगिक हादसे के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर सुरक्षा मानकों की निगरानी कौन कर रहा था? क्या यह सिर्फ तकनीकी खामी थी या लापरवाही की परतें अभी और खुलनी बाकी हैं? फिलहाल पुलिस और प्रशासन जांच में जुटे हैं, लेकिन यह साफ है कि इस हादसे ने औद्योगिक सुरक्षा व्यवस्था की हकीकत को उजागर कर दिया है—जहां एक चूक, कई जिंदगियों पर भारी पड़ गई।

सीएम का सख्त रुख, मजिस्ट्रियल जांच के आदेश

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने घटना को गंभीरता से लेते हुए मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ श्रम कानूनों के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। राज्य सरकार ने मृतकों के परिजनों को 5–5 लाख रुपये और घायलों को 50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। वहीं प्रधानमंत्री राहत कोष (PMNRF) से भी मृतकों के परिवारों को 2 लाख और घायलों को 50 हजार रुपये देने का ऐलान किया गया है।

कंपनी का ऐलान : मुआवजा और नौकरी

हादसे के बाद बढ़ते दबाव के बीच वेदांता प्रबंधन ने भी बड़ा ऐलान किया है। कंपनी ने प्रत्येक मृतक के परिजन को 35–35 लाख रुपये मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की बात कही है। इसके अलावा घायलों को 15–15 लाख रुपये की सहायता राशि देने का आश्वासन दिया गया है।

अस्पतालों में जिंदगी की जंग जारी

घायलों का इलाज रायगढ़ और रायपुर के विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है। रायगढ़ के बालाजी मेट्रो अस्पताल में कई मजदूरों की हालत गंभीर बनी हुई है, जबकि कुछ घायलों को रायपुर के निजी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है।

शातिर बदमाश के साथ जन्मदिन मनाना सिपाही को पड़ा महंगा

नई दृष्टिबिंदु / भिलाई

पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल ने थाना छावनी में पदस्थ आरक्षक नितिन सिंह को निलंबित कर दिया है। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार छावनी थाना क्षेत्र के कैम्प–2 निवासी एक शातिर बदमाश जिसे प्रशासन ने जिला बदर से दंडित किया था। उसका जन्म दिन मनाते हुए छावनी थाने के आरक्षक नितिन सिंह का वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था।

वायरल वीडियो पुलिस मुख्यालय रायपुर तक पहुंचा। आला अफसरों की सख्त नाराजगी के बाद पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल ने छावनी थाना के आरक्षक नितिन सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। सूत्रों ने बताया कि नितिन सिंह को लेकर पहले भी काफी शिकायतें आती रही हैं। कुछ थाना प्रभारियों का बेहद करीबी आरक्षक नितिन वायरल वीडियो और फोटो में शातिर बदमाश के साथ जन्मदिन का उल्लास मनाते दिख रहा है।

आईपीएल सट्टा रैकेट का भंडाफोड़, 20 आरोपी गिरफ्तार

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां क्राइम ब्रांच ने ऑनलाइन सट्टेबाजी के खिलाफ अब तक की बड़ी कार्रवाई करते हुए एक अंतरराज्यीय नेटवर्क का पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस ने उड़ीसा और महाराष्ट्र में एक साथ दबिश देकर कुल 20 सटोरियों को गिरफ्तार किया है।

बताया जा रहा है कि ये पूरा गिरोह आईपीएल के हर मैच पर ऑनलाइन सट्टा चला रहा था और इसके लिए कई डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जा रहा था। पुलिस जब आरोपियों तक पहुंची तो मौके से 82 मोबाइल फोन, 10 लैपटॉप और करीब 60 लाख रुपये का सामान बरामद किया गया। जांच में करोड़ों रुपये के लेनदेन के सबूत भी सामने आए हैं। कई बैंक खातों में भारी ट्रांजेक्शन मिले हैं, जिनकी अब गहराई से जांच की जा रही है। रायपुर पुलिस की इस बड़ी कार्रवाई से ऑनलाइन सट्टा माफियाओं में हड़कंप मच गया है। आने वाले दिनों में इस मामले में और बड़े खुलासे हो सकते हैं।

दुर्ग में म्यूल अकाउंट का जाल ध्वस्त : 1.88 करोड़ की साइबर ठगी का खुलासा, 11 गिरफ्तार

दुर्ग। साइबर अपराध के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत दुर्ग पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। म्यूल खातों के जरिए हो रही साइबर ठगी के मामले में पुलिस ने 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जांच में 250 से अधिक संदिग्ध बैंक खातों में कुल 1 करोड़ 88 लाख 67 हजार 554 रुपये के लेनदेन का खुलासा हुआ है। पुलिस के अनुसार, भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा संचालित समन्वय पोर्टल से प्राप्त जानकारी के आधार पर थाना मोहन नगर और सुपेला पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की। जांच के दौरान कर्नाटका बैंक (स्टेशन रोड, दुर्ग) के 111 खातों और फेडरल बैंक (दक्षिण गंगोत्री, सुपेला) के 105 खातों सहित कुल 250 से अधिक खातों की पड़ताल की गई, जिनका उपयोग साइबर ठगी की रकम प्राप्त करने के लिए किया जा रहा था। पुलिस जांच में यह सामने आया कि खाताधारक अवैध लाभ कमाने के लिए अपने बैंक खातों को साइबर ठगों को उपलब्ध कराते थे। वर्ष 2026 के पहले चार महीनों में ही ऐसे मामलों में 150 से अधिक आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इस मामले में थाना मोहन नगर में अपराध क्रमांक 07/2025 और थाना सुपेला में अपराध क्रमांक 32/2025 के तहत भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर विवेचना की जा रही है। गिरफ्तार सभी 11 आरोपियों को न्यायालय में पेश कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। जब्त सामग्री में मोबाइल फोन, बैंक पासबुक और खातों से संबंधित दस्तावेज शामिल हैं।

सेना के जवान के साथ लाखों की ठगी

बालोद। जिले में आर्मी जवान के साथ ठगी का मामला सामने आया है। अर्जुन्दा थाना क्षेत्र के ग्राम ओडारसकरी निवासी जवान गुंडरदेही स्थित एक निजी बैंक में 2 लाख रुपये के लोन के लिए आवेदन करने पहुंचा था। आरोप है कि बैंक में पदस्थ कर्मचारी रेखराम साहू ने हेरफेर करते हुए 2 लाख की जगह 17 लाख रुपये का लोन सैंक्शन करवा दिया। जैसे ही जवान के खाते में लोन की राशि आई, आरोपी ने किसी अन्य खाते में 15 लाख 50 हजार ट्रांसफर करवा लिए। जवान की पोस्टिंग जम्मू–कश्मीर में है। बैंक से लोन की किस्त जमा करने के लिए दबाव आया तब जाकर ऑर्मी जवान को पता चला कि उन्होंने 2 लाख का लोन लेने आवेदन किया है। लेकिन उनके नाम से 17 लाख का लोन निकाल लिया गया है। ठगी होने की जानकारी पर ऑर्मी जवान ने गुंडरदेही थाने पहुंचकर शिकायत दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गुंडरदेही टीआई नवीन बोरकर ने बताया कि आर्मी जवान के साथ ठगी का मामला संज्ञान में आया है। प्राइवेट बैंक के रेखराम साहू के खिलाफ धारा 318(4) के तहत मामला दर्ज किया गया है। मामले में पुलिस जांच कर रही है।

गीता छात्रों में नैतिक मूल्यों का संचार करती है, डेढ़ सौ बच्चों ने दी परीक्षा 18 बच्चों का चयन

केंद्रीय विद्यालय दुर्ग में गीता क्विज का हुआ आयोजन

नई दृष्टिबिंदु / दुर्ग

गीता प्रचार अभियान के अंतर्गत पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय दुर्ग में एक प्रेरणादायक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों में के शिक्षण, नैतिक मूल्यों के विकास तथा भारतीय सांस्कृतिक परंपराओं के प्रचार-प्रसार को सुदृढ़ करना रहा। इस अवसर पर गीता क्विज 2025 का आयोजन (अंतरराष्ट्रीय श्रीकृष्ण भावनामृत संघ) इस्कॉन द्वारा किया गया, जिसकी स्थापना ने की थी। इस आयोजन में जिले के विभिन्न प्रमुख विद्यालयों के विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।

केंद्रीय विद्यालय दुर्ग के विद्यार्थियों का प्रदर्शन विशेष रूप से सराहनीय रहा। विद्यालय के 18 प्रतिभाशाली विद्यार्थियों आरव, नुराज, अभ्युदय, ओम, मोक्षित, हिमांशु, खुशी, देविका, मयंक, शौर्य, दिव्यांश, अक्षत, सान्या, अर्णभ, आराध्य, काव्यांश एवं आस्तिक का चयन प्रतियोगिता के द्वितीय चरण हेतु किया गया है। प्रतियोगिता का द्वितीय चरण ऑनलाइन माध्यम से आयोजित किया जाएगा, जिसके मई के प्रथम सप्ताह में संपन्न होने की संभावना है। इस उपलब्धि से विद्यालय परिवार एवं अभिभावकों में हर्ष का वातावरण है।

इस अवसर पर डॉ. अजय आर्य ने अपने वक्तव्य में कहा कि गीता का अध्ययन केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में मार्गदर्शन प्रदान करने वाला है। ऐसे आयोजन विद्यार्थियों में नैतिकता, अनुशासन एवं आत्मविश्वास के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

अभिषेक ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि गीता के सिद्धांतों को बाल्यावस्था से ही जीवन में अपनाने से विद्यार्थियों में सकारात्मक सोच एवं सही निर्णय लेने की क्षमता विकसित होती है। इस प्रकार के कार्यक्रम समाज में नैतिक मूल्यों के प्रसार के लिए अत्यंत आवश्यक हैं।

प्रभारी प्राचार्य नीति दास ने सभी चयनित विद्यार्थियों को शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। इस प्रकार के आयोजन विद्यार्थियों में गीता के सिद्धांतों के प्रति रुचि उत्पन्न करने के साथ-साथ उनके नैतिक, आध्यात्मिक एवं व्यक्तित्व विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

खास खबर

लोक कथाएं आज के कथा साहित्य की जननी-गुलबीर सिंह भाटिया

नई दृष्टिबिंदु / भिलाई-दुर्ग

विश्व विरासत दिवस के उपलक्ष में भारतीय सांस्कृतिक निधि (इंटैक) के दुर्ग-भिलाई अध्याय द्वारा आयोजित 'लोक कथा कथन' में 10 राज्यों के सम्बंधित लोक भाषा के जानकार साहित्यकारों ने 12 लोक कथाओं सुनाई 'इस आयोजन में देश के प्रतिष्ठित कथाकार गुलबीर सिंह भाटिया ने मुख्य वक्ता के रूप में अपने विशेषज्ञ उद्बोधन में लोक कथाओं के साहित्यिक, सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, "हम पुरखों के ऋणी हैं जिन्होंने लिपि के अभाव में भी कथा को जीवन दिया और उन कथाओं को जीवित रखा जो हमारे आज के कथा साहित्य की जड़ भी है, मूल भी है ।" उन्होंने मत व्यक्त किया कि लोक कथाएं आज के कथा साहित्य की जननी है। 'एक टोकरी भर मिट्टी' कहानी को वह प्रवेश द्वार बतलाया जिससे होकर हमारी लोक कथा आधुनिक कहानी में प्रवेश करती है।

छत्तीसगढ़ प्रदेश साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष वरिष्ठ साहित्यकार रवि श्रीवास्तव ने अध्यक्षता करते हुए कहा कि आज की कहानी लोक कथाओं की नींव पर खड़ी है। इस विरासत को सहेजने की जरूरत है ताकि लोक कथाओं की अनुगूंज आगामी सदियों तक गूंजती रहे। आरंभ में इंटैक की दुर्ग-भिलाई अध्याय की संयोजिका डॉ हंसा शुक्ला ने अतिथियों का स्वागत करते हुए लोक कथाओं को महत्वपूर्ण साहित्यिक-सांस्कृतिक धरोहर बतलाया 'कार्यक्रम का संचालन करते हुए शिक्षाविद डॉ डी एन शर्मा ने कहा कि हजारों वर्षों पूर्व जन्मी लोक कथाएं हमारी अनमोल अमूर्त धरोहर हैं। उन्होंने दुःख व्यक्त किया कि हमारी पीढ़ी की गलती से नई पीढ़ी मोबाइल के जरिए कार्टून, यूट्यूब, सोशल मीडिया में मस्त होकर लोक कथाओं से अनभिज्ञ है।

सुप्रसिद्ध वरिष्ठ साहित्यकार परदेसी राम वर्मा ने रंगभेद, जातिवाद, ऊंचझनीच के खिलाफ छत्तीसगढ़ में लोकप्रिय 'करिया मुसवा पंडरा मुसवा' छत्तीसगढ़ी लोककथा रोचक ढंग से बतलाई । प्रतिष्ठित कवियत्री संतोष झांझी ने पंजाब में लोकप्रिय भगवान में विश्वास को स्थापित करती पंजाबी लोक कथा 'रजनी' को सुनाया । प्रसिद्ध कवियत्री विद्या गुप्ता ने मध्यप्रदेश के निवाड़ क्षेत्र में प्रचलित निमाड़ी लोककथा 'राजा भरथरी' का रोचक कथन किया। चर्चित कवि शरद कोकास ने महाराष्ट्र प्रांत की मराठी लोककथा 'बट्टे की खीर' का एकल अभिनय कर प्रस्तुति की। युवा साहित्यकार जोस एंथोनी ने केरल की एक मलयालम लोक कथा ह्यागेरा खरगोशह्न को सुनाया। कहानीकार शिवनाथ शुक्ला ने उत्तर प्रदेश में कही जाने वाली लोककथा ह्यसुख की मुरली दुख की मुरलीह्न को प्रभावी ढंग से सुनाया। हिंदी व बंगाली भाषा के साहित्यकार गोविंद पाल ने बंगाल की दो भाइयों के संपत्ति बंटवारे से संबंधित बंगाली लोककथा को सुनाई । देवरी (डौंडीलोहारा) से आए केशव शर्मा ने राजस्थान में लोकनायक तेजा पर केंद्रित लोककथा ह्यवचन के पक्केह्न कही । उड़ियाझभाषी रविंद्र साहू ने 'ठगराज' नामक उड़िसा की लोककथा सुनाई। तेलगुभाषी सुश्री डी नागमणि ने आंध्रप्रदेश में प्रचलित भगवान वेंकटेश्वर से जुड़ी लोककथा ह्यगोविंदा गोविंदाह्न को सुनाया। सांस्कृतिकर्मी डॉ डीपी देशमुख ने छत्तीसगढ़ की रोचक लोककथा ' मारे मुसुवईन ला' का कथन किया । प्रीति अजय बेहरा ने उड़ीसा में भगवान जगन्नाथ से जुड़ी उड़िया ह्यअगहन वृहस्पतिह्न लोककथा को बतलाया ।

कार्यक्रम में प्रदीप भट्टाचार्य, डॉ पी सी पंडा, महेश चतुर्वेदी, , राजेन्द्र राव, बी पोलम्मा, सहदेव देशमुख, शानू मोहनन, रविंद्र खंडेलवाल, कांतिभाई सोलंकी, विश्वास तिवारी, जगमोहन सिन्हा, सरस्वती विशेष रूप से उपस्थित रहे ।

महापौर अलका ने निकाली लॉटरी, 16 हितग्राहियों को मिला प्रधानमंत्री आवास

नई दृष्टिबिंदु / दुर्ग

प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत नगर पालिक निगम दुर्ग क्षेत्र में सरस्वती नगर एवं मां कर्मा बोरसी स्थित अलढ घटक के तहत निर्मित आवासों का आज पारदर्शी लॉटरी प्रक्रिया के माध्यम से आवंटन किया गया।

निगम द्वारा निर्मित ये आवास कम कीमत में आधुनिक सुविधाओं से युक्त हैं, जिन्हें शीघ्र ही पूर्ण रूप से आबाद करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। आवास प्राप्त करने हेतु हितग्राहियों द्वारा लगातार आवेदन किए जा रहे हैं तथा प्रत्येक माह लॉटरी के माध्यम से निष्पक्ष चयन किया जाता है। लॉटरी प्रक्रिया में सरस्वती नगर के 9 एवं मां कर्मा बोरसी के 7 आवासों हेतु कुल 16 आवेदन प्राप्त हुए थे।

महापौर श्रीमती अलका बाघमार ने अधिकारियों, कमर्चारियों एवं हितग्राहियों की उपस्थिति में लॉटरी निकालकर आवासों का आवंटन किया। इस दौरान सीनियर सिटीजन एवं गंभीर बीमार हितग्राहियों को प्राथमिकता देते हुए ग्राउंड फ्लोर के आवास प्रदान किए गए, वहीं अन्य हितग्राहियों को लॉटरी के अनुसार आवास आवंटित किया गया। हितग्राहियों ने स्वयं पर्ची निकालकर अपने आवास का चयन किया, जिससे पूरी प्रक्रिया की पारदर्शिता एवं निष्पक्षता स्पष्ट रूप से परिलक्षित हुई।

महापौर श्रीमती बाघमार ने बताया कि संपूर्ण राशि जमा करने के पश्चात हितग्राहियों को आधिपत्य पत्र प्रदान किया जाएगा। इस अवसर पर सहायक अभियंता संजय ठाकुर, CLTC टिकेश्वर साहू,दीपक संचेती, सचिन ताम्रकार, हिमांशु बेलेंद्र, सहित निशा बालवे व टीम एवं निगम के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।

पेवर ब्लॉक लगाने महापौर शशि सिन्हा ने किया भूमिपूजन

रिसाली। महापौर शशि सिन्हा की निधि से वार्ड 29 लक्ष्मी नगर स्थित सतनाम भवन परिसर में पेवर ब्लॉक लगाया जाएगा। इस कार्य के महापौर ने अपने निधि से 1 लाख 50 हजार की स्वीकृत की है। उन्होंने इस कार्य के लिए गुरुवार को भूमिपूजन किया। महापौर शशि सिन्हा ने इस अवसर पर उपस्थित लोगों से कहा कि प्राथमिकता के आधार पर वे कार्य स्वीकृत कर रही है और विकास कार्य को मूर्त रूप देने भूमिपूजन भी साथ ही साथ कर रही है। भूमिपूजन कार्यक्रम में एम आई सी संजू नेताम समेत समाज के वरिष्ठ नागरिक और पदाधिकारी उपस्थित थे।

बढ़ती गर्मी को देखते हुए स्कूलों में ग्रीष्मकालीन अवकाश या समय परिवर्तन की मांग

नई दृष्टिबिंदु / दुर्ग

प्रदेश में लगातार बढ़ती भीषण गर्मी को देखते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी छत्तीसगढ़ के सचिव अय्यूब खान के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर जनदर्शन कार्यक्रम में ज्ञापन सौंपा। अय्यूब खान ने बताया कि वर्तमान में प्रदेश सहित जिले में तापमान तेजी से बढ़ते हुए 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, और आने वाले दिनों में इसके और बढ़ने की संभावना है। ऐसी स्थिति में स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

ज्ञापन के माध्यम से कलेक्टर के जरिए राज्य सरकार, मुख्यमंत्री विष्णु देव साय एवं शिक्षा मंत्री गजेन्द्र यादव से मांग की गई है कि प्रदेश के सभी शासकीय एवं निजी स्कूलों में ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित किया जाए अथवा स्कूलों के समय में परिवर्तन किया जाए।

उन्होंने सुझाव दिया कि स्कूलों का संचालन सुबह 7:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक ही किया जाए। साथ ही सुबह 8 बजे के बाद खुले मैदान या धूप में होने वाली सभी गतिविधियों को तत्काल प्रभाव से बंद करने के निर्देश जारी किए जाएं।

अय्यूब खान ने कहा कि छोटे बच्चों सहित सभी विद्यार्थियों के स्वास्थ्य, शारीरिक एवं मानसिक विकास को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय अत्यंत आवश्यक है। कई स्कूलों से शिकायतें मिल रही हैं कि गर्मी के कारण बच्चों को अत्यधिक परेशानी हो रही है, विशेषकर बहुमंजिला भवनों में जहां पंखे और कूलर भी प्रभावी नहीं हैं। साथ ही, बढ़ती विद्युत कटौती की समस्या भी स्थिति को और गंभीर बना रही है।

उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि बच्चों के हित में शीघ्र निर्णय लेते हुए स्कूलों का समय सुबह निर्धारित कर दोपहर 12 बजे तक बंद करने के निर्देश जारी किए जाएं। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल में प्रमुख रूप से अय्यूब खान, पुरुषोत्तम सोनवानी, वरिष्ठ कांग्रेस नेता मो. रफीक, जसवंत गायकवाड एवं बलविंदर सिंह उपस्थित थे।

डॉ.आंबेडकर जयंती पर रक्तदान शिविर का आयोजन

दुर्ग। महामानव मल्टीपर्पस सोसायटी द्वारा विश्वरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जी की 135वीं जयंती के अवसर पर स्व. पांडुरंग रामराव डोनगांवकर शासकीय जिला चिकित्सालय दुर्ग में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जी के छायाचित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में डॉ. मनोज दानी (जिला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी) तथा विशेष अतिथि डॉ. आशीषन मिंज (सिविल सर्जन, जिला चिकित्सालय दुर्ग), डॉ. जे.पी. मेश्राम (ब्लड बैंक नोडल अधिकारी) एवं डॉ. अखिलेश यादव उपस्थित रहे।

महापौर अलका ने किया सिकोला नाला निर्माण कार्य का निरीक्षण

नई दृष्टिबिंदु / दुर्ग

नगर पालिक निगम दुर्ग की महापौर श्रीमती अलका बाघमार द्वारा आज निगम क्षेत्र अंतर्गत अधोसंरचना मद से किए जा रहे सिकोला नाला निर्माण कार्य (लागत राशि लगभग 316.62 लाख रुपये) का स्थल निरीक्षण किया गया। इस दौरान लोक कर्म प्रभारी देव नारायण चन्द्राकर, कार्यपालन अभियंता विनीता वर्मा, सहायक अभियंता संजय ठाकुर, उपअभियंता पंकज साहू एवं ठेकेदार एजेंसी के प्रतिनिधि नंद कुमार चंद्राकर उपस्थित रहे।

निरीक्षण के दौरान महापौर ने निर्माण कार्य की प्रगति और गुणवत्ता का जायजा लेते हुए अधिकारियों एवं ठेकेदार को स्पष्ट निर्देश दिए कि कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य की गति तेज की जाए और निर्धारित समय-सीमा में ही कार्य पूर्ण किया जाए, ताकि शहरवासियों को शीघ्र बेहतर जल निकासी व्यवस्था का लाभ मिल सके।

महापौर ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे नियमित रूप से फील्ड में उपस्थित रहकर कार्य की निगरानी करें तथा गुणवत्ता की समय-समय पर जांच सुनिश्चित करें। उन्होंने विशेष रूप से नाले के स्लोप और लेवल को सही बनाए रखने, दीवारों की मोटाई एवं सरियों के बीच की दूरी को निर्धारित मानकों के अनुरूप रखने के निर्देश दिए। उन्होंने यह भी कहा कि निर्माण सामग्री की गुणवत्ता से किसी प्रकार का समझौता न किया जाए और कार्य पूर्णतः तकनीकी मापदंडों के अनुसार ही संपन्न किया जाए। बरसात के पूर्व अधिकतम कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित करते हुए उन्होंने कार्य में तेजी लाने पर जोर दिया।

लगभग 1700 मीटर लंबाई वाले इस नाला निर्माण कार्य के पूर्ण होने से शहर की जल निकासी व्यवस्था सुदृढ़ होगी और वर्षा ऋतु में जलभराव की समस्या से नागरिकों को राहत मिलेगी। महापौर ने कहा कि यह परियोजना शहर के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसमें पारदर्शिता एवं मजबूती सुनिश्चित करना सभी संबंधितों की जिम्मेदारी है। उन्होंने अधिकारियों एवं ठेकेदार को निर्देशित किया कि निर्माण कार्य में किसी भी प्रकार की तकनीकी त्रुटि पाए जाने पर तत्काल सुधार किया जाए, ताकि गुणवत्तापूर्ण एवं टिकाऊ निर्माण सुनिश्चित हो सके।

प्रशासनिक पहल शुरु, भिलाई में बनेगा सुव्यवस्थित थोक सब्जी मार्केट

आकाशगंगा थोक सब्जी मार्केट पहुंचे संभाग आयुक्त और कलेक्टर, पैदल भ्रमण कर वस्तुस्थिति का लिया जायजा

नई दृष्टिबिंदु / भिलाई

भिलाई नगर में आकाशगंगा थोक सब्जी मार्केट के विकल्प के रूप में सुव्यवस्थित थोक सब्जी मार्केट का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए प्रशासनिक पहल शुरू हो गई है। संभाग आयुक्त सत्यनारायण राठौर और कलेक्टर अभिजीत सिंह नगर निगम भिलाई एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ चिन्हांकित स्थल राधिका नगर भिलाई, पुलिस थाना सुपेला के पीछे रिक्त मैदान का मौका मुआयना किये।

निगम आयुक्त राजीव पाण्डेय ने अवगत कराया कि उक्त स्थान भिलाई निगम के अंतर्गत है, इसे पूर्व में साडा द्वारा टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग को आवासीय फ्लैट हेतु उपलब्ध कराया गया है। वर्तमान में उक्त स्थल निगम अंतर्गत है। इसे व्यवसायिक उपयोग हेतु परिवर्तित कर थोक सब्जी मार्केट हेतु विकसित किया जाना है। स्थल मुआयना के दौरान संभाग आयुक्त श्री राठौर और कलेक्टर श्री सिंह ने मौके पर चिन्हांकित स्थल के नक्शे में खसरे एवं रकबा का अवलोकन भी किया। तत्पश्चात उन्होंने आकाशगंगा थोक सब्जी मार्केट में पैदल भ्रमण कर स्थिति का जायजा लिया। साथ ही, व्यापारियों से मार्केट की व्यवस्था एवं व्यवस्थापन के संबंध में चर्चा की।

व्यापारियों ने बताया कि मार्केट अंतर्गत लगभग 456 बड़ी दुकाने एवं 300 के करीब छोटी व्यवसायिक दुकाने हैं। यहां प्रतिदिन प्रदेश के विभिन्न क्षेत्र से बड़ी वाहनों में सब्जियां आयतित होती है। वहीं जिले के किसान भी छोटी गाड़ियों से अपनी सब्जियां यहां बेचने के लिए लाते है। प्रतिदिन सुबह 4 बजे से 10 बजे तक वाहनों के आगमन व अव्यवस्थित पार्किंग की वजह से व्यापारियों एवं क्रेताओं को परेशानियां झेलनी पड़ती है। उक्त मार्केट में अनेक दुकाने जर्जर अवस्था में है। साथ ही, अवैध कब्जे के रूप में दुकाने संचालित की जा रही है।

मार्केट से पानी निकासी का भी समुचित प्रबंध का अभाव है। मार्केट अवलोकन पश्चात संभाग आयुक्त और कलेक्टर ने भिलाई के प्रियदर्शनी परिसर में निर्माणाधीन स्वीमिंग पुल, स्केटिंग ट्रैक, नालंदा परिसर, हॉर्स राईडिंग ग्राउण्ड का भी अवलोकन किए। साथ ही, नेहरू नगर अण्डरब्रिज से सुपेला अण्डरब्रिज तक लगभग 3 किमी सर्विस लेन का भी निरीक्षण किए। उन्होंने निर्माण कार्यों में प्रगति लाने व समयावधि में कार्य पूर्ण करने अधिकारियों को निर्देशित किया। इस अवसर पर नगर निगम भिलाई के आयुक्त राजीव पाण्डेय, एसडीएम भिलाई महेश राजपूत और भिलाई निगम एवं राजस्व विभाग के अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

ईद मिलन में समाज के उत्थान पर की चर्चा, सदस्यों को दिए उपहार

नई दृष्टिबिंदु / भिलाई

इस्पात नगरी भिलाई की मुस्लिम महिलाओं के गैर सरकारी संगठन अल मदद एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी का ईद मिलन समारोह स्थानीय स्तर पर शानदार ढंग से मनाया गया। आयोजन में सभी सदस्यों ने हिस्सा लिया। बच्चों ने अपनी तकरीर और नात शरीफ पेश कर महफि ल को रोशन कर दिया। सभी मेहमानों का इस्तकबाल किया गया।

डॉ. माहीन फातिमा अली ने अपने शायराना अंदाज से पूरी महफिल में समा बांध दिया। रिहान खान ने स्वागत भाषण दिया। अफशीन अली ने अल मदद सोसाइटी के कार्यों पर रोशनी डाली। सोसायटी की निदेशक अंजुम अली ने हर एक सदस्य का गमजीशी से स्वागत किया और उपहार देकर खुशियां बांटी। आयोजन को सफलतापूर्वक सम्पादित करने में दरख्शां, शमीम अशरफी, नरगिस और रूबीना का विशिष्ट योगदान रहा। आखिर में सभी सदस्यों ने एक साथ बैठ कर डिनर किया और सेवइयों का लुत्फ उठाया। इस दौरान समाज के उत्थान के लिए नई योजनाएं और बेहतर भविष्य के लिए भी चर्चा की गई।

अब हथियार नहीं, हुनर से बदल रही पुर्नवासितों की जिंदगी : दिया जा रहा प्रशिक्षण

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

कोंडागांव जिले में राज्य शासन की पुर्नवास नीति से पुर्नवासित व्यक्तियों की जिंदगी को नई दिशा मिल रही है। कभी हिंसा के रास्ते पर भटके युवा अब मुख्यधारा में लौटकर कौशल विकास के माध्यम से आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।

इसी क्रम में ग्राम कुधुर के तुलसी राम, रजमन एवं गोबरू वतर्मान में जिले में संचालित पुनर्वास केन्द्र में रहकर लाइवलीहुड कॉलेज के माध्यम से इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। तुलसी राम कश्यप ने बताया कि पूर्व में क्षेत्र में भय और असुरक्षा के माहौल के कारण वे संगठन से जुड़ गए थे, किन्तु राज्य शासन की पुर्नवास नीति से प्रेरित होकर उन्होंने आत्मसमर्पण कर मुख्यधारा में लौटने का निर्णय लिया। वर्तमान में वे पुर्नवास केन्द्र में रहकर कौशल उन्नयन प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में वायरिंग का दो माह का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें लगभग 15 दिवस का प्रशिक्षण पूर्ण हो चुका है। प्रशिक्षण उपरांत वे अपने क्षेत्र में ही स्वरोजगार के रूप में वायरिंग कार्य प्रारंभ करने की योजना बना रहे हैं। इसी प्रकार रजमन एवं गोबरू ने भी पुर्नवास नीति के अंतर्गत आत्मसमर्पण कर मुख्यधारा में लौटने का निर्णय लिया। वतर्मान में वे भी इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। उनका कहना है कि प्रशिक्षण पूर्ण होने के बाद वे अपने गांव में स्वरोजगार स्थापित कर आय अर्जित करेंगे एवं अपने परिवार का भरण-पोषण करेंगे।

तीनों युवाओं ने राज्य शासन की पुर्नवास नीति के प्रति संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि इस पहल से उन्हें नया जीवन प्रारंभ करने का अवसर मिला है। पहले जहां भय एवं अस्थिरता का माहौल था, वहीं अब वे सुरक्षित वातावरण में प्रशिक्षण प्राप्त कर अपने भविष्य के प्रति आश्वस्त हैं। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य शासन द्वारा संचालित पुनर्वास नीति के अंतर्गत आत्मसमर्पण करने वाले व्यक्तियों को मुख्यधारा से जोड़ते हुए उन्हें कौशल विकास, रोजगार एवं आजीविका के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

जिला प्रशासन द्वारा संचालित पुनर्वास केन्द्र इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, जहां पूर्व में भटके हुए युवाओं को प्रशिक्षण एवं मार्गदर्शन प्रदान कर उन्हें समाज की मुख्यधारा में पुनः स्थापित किया जा रहा है।

खास खबर

भीषण गर्मी को देखते हुए ग्रीष्मकालीन अवकाश में संशोधन, अब 20 अप्रैल से 15 जून तक रहेगा स्कूलों में अवकाश

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

प्रदेश में बढ़ती भीषण गर्मी और लू के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए बच्चों के स्वास्थ्य की सुरक्षा को सवीच्च प्राथमिकता देते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर स्कूलों के ग्रीष्मकालीन अवकाश की अवधि में आंशिक संशोधन किया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि बढ़ती भीषण गर्मी में बच्चों की सेहत की सुरक्षा हर हाल में सुनिश्चित करना हम सब की जिम्मेदारी है। बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पूर्व निर्धारित ग्रीष्मकालीन अवकाश को पहले लागू करने का निर्णय लिया है, ताकि इस भीषण गर्मी में बच्चों की सेहत सुरक्षित रह सके।

स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर द्वारा जारी आदेश के अनुसार, पूर्व में दिनांक 01 मई 2026 से 15 जून 2026 तक घोषित ग्रीष्मकालीन अवकाश में संशोधन करते हुए अब दिनांक 20 अप्रैल 2026 से 15 जून 2026 तक अवकाश घोषित किया गया है। यह आदेश प्रदेश के समस्त शासकीय, अनुदान प्राप्त, गैर अनुदान प्राप्त एवं अशासकीय शालाओं पर लागू होगा।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कचहरी चौक स्थित एसबीआई के नये भवन का किया शुभारंभ

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने राजधानी रायपुर के कचहरी चौक स्थित भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की कचहरी शाखा के नवीन एवं अत्याधुनिक परिसर का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्य महाप्रबंधक प्रभाष कुमार सुबुद्धि, उप महाप्रबंधक रमेश सिन्हा, प्रबंधक अनिल यादव सहित बैंक के अधिकारी-कमचर्चारी उपस्थित रहे। साय ने कहा कि यह अत्यंत हर्ष और सौभाग्य का विषय है कि पिछले 50 वर्षों से संचालित एसबीआई की कचहरी शाखा अब नए आधुनिक भवन में स्थानांतरित होकर ग्राहकों को और बेहतर सेवाएं प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि इस नए परिसर में उपभोक्ताओं को अत्याधुनिक बैंकिंग सुविधाएं मिलेंगी, जिससे उनके कार्य और अधिक सहज और त्वरित होंगे। श्री साय ने बैंकिंग व्यवस्था को देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बताते हुए कहा कि भारतीय स्टेट बैंक अपने दायित्वों का उत्कृष्ट निर्वहन कर रहा है और आगे भी ग्राहकों की सेवा में इसी तरह अग्रणी भूमिका निभाता रहेगा। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर शाखा के अधिकारियों और ग्राहकों को शुभारंभ की बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। उल्लेखनीय है कि एसबीआई की कचहरी शाखा ने हाल ही में अपनी सेवाओं के 50 वर्ष पूर्ण किए हैं। ग्राहकों को बेहतर, सुविधाजनक और उन्नत बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शाखा को पंडरी रोड स्थित आक्सीजोन क्षेत्र में नए परिसर में स्थानांतरित किया गया है, जहां आधुनिक सुविधाओं के साथ बेहतर बैंकिंग अनुभव सुनिश्चित किया जाएगा।

गांव में ही मिला न्याय—अकलाडोंगरी लिंक कोर्ट से राजस्व मामलों का त्वरित समाधान

रायपुर। धमतरी जिला प्रशासन द्वारा दूरस्थ और डूबान प्रभावित क्षेत्रों में राजस्व सेवाओं को सरल एवं सुलभ बनाने की दिशा में किया जा रहा नवाचार अब प्रभावी परिणाम देने लगा है। जीप ।प्रशासन के मार्गदर्शन में ग्राम पंचायत भवन अकलाडोंगरी में आयोजित लिंक कोर्ट के माध्यम से आज कई राजस्व प्रकरणों का मौके पर ही त्वरित निराकरण किया गया, जिससे ग्रामीणों को बड़ी राहत मिली। लिंक कोर्ट की कायर्वाही में बड़ी संख्या में ग्रामीण अपने आवेदन लेकर पहुंचे। पीठासीन अधिकारी ने संवेदनशीलता और तत्परता के साथ सुनवाई करते हुए त्रुटि सुधार के 3 मामलों का तत्काल निराकरण किया। इसके अलावा फौती नामांतरण के 2, क्रय-विक्रय आधारित नामांतरण के 2, भूमि सीमांकन का 1 तथा खाता विभाजन का 1 नया आवेदन प्राप्त हुआ।

देश और राज्य के भविष्य की दिशा तय करने का आधार है जनगणना : मुख्यमंत्री साय

मुख्यमंत्री ने जनगणना 2027 के तहत ऑनलाइन स्व-गणना कर राज्य स्तरीय अभियान का किया शुभारंभ

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास में जनगणना 2027 के तहत ऑनलाइन स्व-गणना कर जनगणना अभियान का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने स्वयं पोर्टल पर अपनी जानकारी दर्ज कर नागरिकों को इस राष्ट्रीय कार्य में सक्रिय भागीदारी का संदेश दिया।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि भारत में विश्व का सबसे बड़ा जनगणना अभियान संचालित हो रहा है और छत्तीसगढ़ में भी आज से ऑनलाइन स्व-गणना की प्रक्रिया शुरू हो गई है। उन्होंने कहा कि नागरिक 16 अप्रैल से 30 अप्रैल 2026 के बीच ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपने परिवार से संबंधित जानकारी स्वयं दर्ज कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस बार जनगणना को आधुनिक और डिजिटल स्वरूप दिया गया है, जिससे प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और सुलभ हो सके।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि जनगणना केवल आंकड़ों का संकलन नहीं, बल्कि देश और राज्य के भविष्य की दिशा तय करने का आधार है। इन आंकड़ों के आधार पर सरकार आने वाले वर्षों की योजनाएं तैयार करती है, ताकि विकास का लाभ हर वर्ग तक प्रभावी रूप से पहुंच सके। मुख्यमंत्री ने बताया कि 1 मई 2026 से जनगणना का पहला चरण शुरू होगा, जिसमें मकान सूचीकरण और गणना का कार्य किया जाएगा। 30 मई तक प्रगणक घर-घर जाकर आवासीय और गैर-आवासीय भवनों, उनकी स्थिति, उपयोग तथा बुनियादी सुविधाओं जैसे पेयजल, शौचालय, बिजली, रसोई गैस, इंटरनेट और संचार व्यवस्था से संबंधित जानकारी एकत्र करेंगे।

उन्होंने प्रदेशवासियों से आग्रह करते हुए कहा कि जब भी प्रगणक घर आएं, तो उन्हें सही, स्पष्ट और पूर्ण जानकारी दें, क्योंकि प्रत्येक जानकारी राज्य के विकास की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उन्होंने कहा कि जनगणना के दौरान दी गई सभी व्यक्तिगत जानकारी पूर्णतः गोपनीय रखी जाती है और इसका उपयोग केवल सांख्यिकीय एवं नीतिगत उद्देश्यों के लिए ही किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ तेजी से विकास के पथ पर अग्रसर है और विकसित छत्तीसगढ़ 2047 के संकल्प को साकार करने में जनगणना की महत्वपूर्ण भूमिका है। सही आंकड़े ही बेहतर योजना और प्रभावी विकास की नींव रखते हैं। उन्होंने प्रदेश के सभी नागरिकों से इस महाअभियान को जनभागीदारी का उत्सव बनाने और सक्रिय सहयोग देने की अपील की।

इस दौरान अपर मुख्य सचिव तथा जनगणना के नोडल मनोज कुमार पिंगुआ, कलेक्टर रायपुर डॉ. गौरव कुमार सिंह, संचालक जनगणना कार्तिकेय गोयल सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे।

स्व-गणना की शुरूआत : अब नागरिक खुद भर सकेंगे अपनी जानकारी-मुख्य सचिव

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

छत्तीसगढ़ में जनगणना 2027 के पहले चरण के तहत मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना के तारतम्य में 16 से 30 अप्रैल 2026 तक स्व-गणना की प्रक्रिया की शुरूआत हुई है। यहां मंत्रालय महानदी भवन में मुख्य सचिव विकासशील ने स्व-गणना के तहत स्वयं अपनी जानकारी दर्ज की। इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव गृह मनोज कुमार पिंगुआ, छत्तीसगढ़ जनगणना निदेशक कातिर्केय गोयल सहित जनगणना निदेशालय के अधिकारी भी मौजूद थे। मुख्य सचिव ने प्रदेशवासियों से अपील की है कि इस सुविधा का अधिक से अधिक उपयोग करें और अपनी जानकारी स्वयं भरकर जनगणना में सक्रिय भागीदारी निभाएं। राज्य में 16 अप्रैल से 30 अप्रैल 2026 तक नागरिकों को स्व-गणना के माध्यम से अपनी जानकारी दर्ज करने का अवसर दिया गया है। आज अपर मुख्य सचिव गृह श्री मनोज कुमार पिंगुआ ने भी स्व-जनगणना के तहत अपनी जानकारी पोर्टल पर जानकारी दर्ज की। स्व-गणना के लिए https://se.census.gov.in/ पोर्टल पर जाकर आसानी से विवरण भरा जा सकता है।

मुख्य सचिव ने कहा है कि यह पहल जनगणना प्रक्रिया को आसान, पारदर्शी और अधिक विश्वनीय बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जिससे लोग अपनी सही और पूरी जानकारी स्वयं साझा कर सकेंगे। स्व-गणना अवधि समाप्त होने के बाद, 1 मई से 30 मई तक जनगणना टीम घर-घर जाकर लोगों से जानकारी एकत्रित करेगी। प्रगणक घर-घर आकर जानकारी दर्ज करेंगे। हर मकान की जानकारी दर्ज की जाएगी। घर की स्थिति, सुविधाएं और मूलभूत जानकारी संकलित की जाएगी। जिन्होंने स्व-गणना के तहत जानकारी दर्ज की है वे जनगणना प्रगणकों के घर आने पर उनसे रए कऊजरूर साझा करें। यदि कोई स्व-गणना नहीं कर पाते है तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। छत्तीसगढ़ राज्य में 1 मई से 30 मई 2026 तक की अवधि में प्रगणक आपके घर आकर जानकारी अवश्य दर्ज करेंगे। सभी नागरिकों से अनुरोध किया गया है कि वे इस अवसर का लाभ उठाकर देश के विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। इस अवसर पर जनगणना निदेशालय के संयुक्त संचालक प्रदीप साव सहित अन्य अधिकारी शामिल हुए।

शराब घोटाले में बड़ा खुलासा : पूर्व विशेष सचिव अरुणपति त्रिपाठी और पत्नी पर आय से अधिक संपत्ति का केस दर्ज

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित 3000 करोड़ रुपये से अधिक के शराब घोटाले में अब जांच ने नया मोड़ ले लिया है। केंद्रीय जांच एजेंसी केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने पहली बार आबकारी विभाग के तत्कालीन विशेष सचिव एवं छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पूर्व प्रबंध संचालक अरुणपति त्रिपाठी और उनकी पत्नी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का मामला दर्ज किया है। सीबीआई ने एफआईआर में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है, जिससे यह स्पष्ट हो गया है कि जांच अब सीधे संपत्ति के खेल तक पहुंच चुकी है।

10 साल में संपत्ति में बेतहाशा उछाल

जांच में सामने आया है कि वर्ष 2013 में अरुणपति त्रिपाठी की कुल संपत्ति जहां 38.08 लाख रुपये थी, वहीं 2023 तक यह बढ़कर 3.32 करोड़ रुपये पहुंच गई। सीबीआई के मुताबिक, दंपत्ति ने इस दौरान अपनी वैध आय से करीब 4.91 करोड़ रुपये अधिक संपत्ति अर्जित की, जो उनकी ज्ञात आय से लगभग 54.53 प्रतिशत ज्यादा है।

आय कम, खर्च ज्यादा-बड़ा अंतर उजागर

जांच अवधि (1 फरवरी 2013 से 22 दिसंबर 2023) के दौरान दंपत्ति की कुल आय करीब 9 करोड़ रुपये आंकी गई, जबकि खर्च 10.97 करोड़ रुपये से अधिक पाया गया। इस खर्च में विदेशी लेन-देन, म्यूचुअल फंड निवेश, कॉर्पोरेट निवेश और निजी खर्च शामिल हैं, जो घोषित आय से मेल नहीं खाते। पूछताछ में त्रिपाठी इन विसंगतियों का संतोषजनक जवाब नहीं दे सके।

तीन दर्जन से ज्यादा अफसर रडार पर

इस कार्रवाई के बाद तीन दर्जन से अधिक अधिकारी जांच के दायरे में आ गए हैं। इससे पहले आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा की जांच में पूर्व मुख्य सचिव विवेक ढांड, पूर्व आईएएस अनिल टूटेजा और निरंजन दास समेत करीब 70 लोगों को आरोपी बनाया जा चुका है। कई मामलों में छापेमारी, गिरफ्तारी और पूछताछ भी हो चुकी है।

दो साल बाद सीबीआई की एंट्री, जांच तेज

शराब घोटाले की जांच पहले प्रवर्तन निदेशालय (ED) कर रहा था, जिसे 21 दिसंबर 2024 को सीबीआई को सौंपा गया। केस ट्रांसफर होने के करीब दो साल बाद अब इस बड़े मामले में आय से अधिक संपत्ति का अपराध दर्ज किया गया है।

कई शहरों में फैली संपत्ति का जाल

जांच एजेंसियों के अनुसार, त्रिपाठी के पास रायपुर के लाभांडी क्षेत्र में फ्लैट, नया रायपुर के प्रीमियम गोल्फ कोर्स इलाके में संपत्ति, दुर्ग जिले में जमीन, भिलाई में मकान के साथ-साथ आभूषण और भारी बैंक बैलेंस मौजूद है।

सिंडिकेट के मास्टरमाइंड पर आरोप

आरोप है कि इंडियन टेलीकॉम सर्विस से प्रतिनियुक्ति पर आए अरुणपति त्रिपाठी ने 2019 से 2023 के बीच सरकारी शराब दुकानों के जरिए अवैध शराब कारोबार को बढ़ावा दिया और पूरे सिंडिकेट के संचालन में अहम भूमिका निभाई। अब बड़ा सवाल - क्या और नाम सामने आएंगे? इस कार्रवाई के बाद यह साफ हो गया है कि शराब घोटाले की जांच अब अपने निर्णायक चरण में प्रवेश कर चुकी है। सवाल यह है कि क्या आने वाले दिनों में और बड़े नाम इस घेरे में आएंगे, या फिर यह मामला भी फाइलों में सिमट कर रह जाएगा।

झारखंड राज्य आवास बोर्ड की 6 सदस्यीय टीम छत्तीसगढ़ पहुंची

रायपुर। झारखंड राज्य आवास बोर्ड की 6 सदस्यीय उच्चस्तरीय टीम अध्ययन प्रवास पर छत्तीसगढ़ पहुंची है। यह दल 15 से 18 अप्रैल 2026 तक राज्य में प्रवास कर छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल की आवासीय योजनाओं, नियमों, प्रक्रियाओं और नवाचारों का विस्तृत अध्ययन करेगा। छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल द्वारा अध्ययन दल को योजनाओं, नीतियों और कार्यप्रणाली से संबंधित विस्तृत जानकारी दी गई। इस दौरान अपर आयुक्त हर्ष कुमार जोशी ने तकनीकी विषयों पर प्रस्तुतीकरण दिया। मुख्य संपदा अधिकारी सुनील कुमार सिंह ने संपत्ति प्रबंधन, मार्केटिंग, विक्रय प्रणाली एवं आईटी आधारित प्रक्रियाओं की जानकारी साझा की। वहीं मुख्य लेखा अधिकारी पूजा मिश्रा शुक्ला ने वित्तीय प्रबंधन पर प्रकाश डाला। उपायुक्त बी.बी. सिंह एवं कार्यपालन अभियंता संदीप साहू ने भी तकनीकी पहलुओं और कार्यप्रणाली से दल को अवगत कराया।

सिलगेर के माड़वी कोसा ने अपने हाथों से बनाया अपना घर, मुख्यमंत्री साय ने सौंपी खुशियों की चाबी

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

ग्राम पंचायत सिलगेर विकासखंड कोन्टा के हितग्राही माड़वी कोसा के लिए वर्षों पुराना सपना अब साकार हो गया है। जो परिवार कभी कठिन परिस्थितियों में जर्जर झोपड़ी में जीवन गुजार रहा था, आज उसी परिवार के पास एक सुरक्षित, सम्मानजनक और मजबूत पक्का आवास है। नियद नेल्लानार योजना एवं प्रधानमंत्री आवास योजनाझ्रग्रामीण के संयुक्त प्रयासों ने उनके जीवन में वह बदलाव ला दिया, जिसने संघर्ष को उम्मीद में बदल दिया।

इस बदलाव की असली नींव बनी रूरल मेसन ट्रेनिंग, जिसे मेरापथ एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा ग्राम पंचायत स्तर पर संचालित किया गया। प्रशिक्षण प्राप्त कर श्री कोसा ने न केवल निर्माण कार्य की तकनीक सीखी, बल्कि आत्मविश्वास के साथ अपने ही हाथों से अपने घर का निर्माण कर दिखाया। यह कहानी केवल एक मकान बनने की नहीं, बल्कि एक व्यक्ति के आत्मनिर्भर बनने और अपने भविष्य को स्वयं गढ़ने की प्रेरक मिसाल बन गई है।

वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत श्री कोसा को 1.20 लाख रुपए की आवास स्वीकृति मिली। इसके साथ ही मनरेगा अभिसरण से 95 मानव दिवस एवं 23,085 रुपए की मजदूरी सहायता प्रदान की गई, जिससे निर्माण कार्य को गति मिली। वहीं स्वच्छ भारत मिशन से 12,000 रुपए की राशि से शौचालय निर्माण, सोलर पैनल से रोशनी की सुविधा और नलझ्रजल व्यवस्था से घर तक स्वच्छ पेयजल उपलब्ध होने से उनके परिवार का जीवन अब सुविधाजनक और सुरक्षित बन गया है। इस प्रेरणादायक परिवर्तन पर कलेक्टर अमित कुमार ने इसे जिले के लिए मॉडल बताते हुए कहा कि योजनाओं का सही क्रियान्वयन और कौशल विकास मिलकर परिवारों को आत्मनिर्भर बना सकते हैं। वहीं जिला पंचायत सीईओ मुकुंद ठाकुर ने इसे सफल उदाहरण बताते हुए कहा कि प्रशिक्षण से गुणवत्ता बढ़ती है और हितग्राही स्वयं सशक्त बनता है। मुख्यमंत्री प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कोसा से संवाद कर उन्हें साल-श्रीफल एवं सांकेतिक चाबी भेंट कर सम्मानित किया। आज माड़वी कोसा का यह पक्का घर केवल ईंट-पत्थर का निर्माण नहीं, बल्कि संघर्ष से सफलता तक की वह कहानी है जो पूरे क्षेत्र को प्रेरणा दे रही है।

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई नगर, तहसील व जिला दुर्ग

-:: ईश्तहार::-

रा.प्र.क्र. 202604101000026 /अ-6/वर्ष 2025-26

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदिका/आवेदक - कुमारी बाई पति स्व. तिलकदास निवासी कुरुद द्वारा ग्राम कोहका प.ह.नं. 45 स्थित भूमि खसरा नंबर 4679 रकबा 0.02 हे. भूमि आवेदक के पति के नाम पर दर्ज है। भूमि स्वामी की मृत्यु हो जाने से भूमिस्वामी का नाम विलोपित कर उनके विधिक वारीसानों का नाम दर्ज किए जाने के संबंध में आवेदन-पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

अतः उक्त संबंध में पर जिस किसी भी व्यक्ति को आपत्ति या उजर दावा हो तो सुनवाई तिथि दिनांक 20.04.2026 तक या उसके पूर्व स्वयं या अपने मान्य अधिवक्तागण के साथ उपस्थित होकर अपना आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पत्र पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 27.03.2026 को मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय के मुहर से जारी किया गया है।

अतिरिक्त तहसीलदार
भिलाई नगर

संपादकीय

डिग्री मतलब रोजगार की गारंटी नहीं है

रोजगार दो क्षेत्रों में मिला करता है। एक सरकारी क्षेत्र और दूसरा निजी क्षेत्र। सरकारी क्षेत्र में रोजगार के अवसर सीमित होते हैं लेकिन ज्यादातर लोग सरकारी नौकरी चाहते हैं और अवसर सीमित होने के कारण सबको सरकारी नौकरी मिलती नहीं है। सरकारी नौकरी की मांग ज्यादा है, इसलिए उसके प्रतिस्पर्धा भी सबसे ज्यादा है ।जो प्रतिस्पर्धा में सफल होते हैं, उनको सरकारी नौकरी मिलती है निजी क्षेत्र मे सरकारी से ज्यादा रोजगार के मौके होते हैं। आदमी के पास किसी भी तरह की योग्यता है, जिसकी निजी क्षेत्र में मांग है तो वहां उसको काम की कमी नहीं है। यही वजह है निजी क्षेत्र में देश के सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार मिलता है।

कई लोग इसलिए उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं कि उनके पास उच्च शिक्षा की डिग्री होगी तो नौकरी तो मिल ही जाएगी। लेकिन कड़वी सच्चाई यह है कि जिनके पास उच्च शिक्षा की डिग्री है उनको भी नौकरी नही मिलती है। यानी डिग्री या उच्चशिक्षा की डिग्री होने का मतलब यह नहीं है कि नौकरी मिलने की गारंटी है छत्तीसगढ़ के रोजगार कार्यालय के आंकड़ों के मुताबिक तो 15 लाख शिक्षित बेरोजगार है, इनमें से 4.7 लाख युवाओं के पास उच्च शिक्षा की डिग्री है, लेकिन उनको नौकरी नहीं मिल रही है। बीई, बीटेक, आईटीआई डिप्लोमा कर बेरोजगारों की संख्या 3.59 लाख है ।उनके पास स्किल है लेकिन उनको नौकरी नहीं मिल रही है। बताया जाता है उनके पास वो स्किल नही है, जिसकी बाजार में मांग है।

कोई भी प्रदेश हो वहां शिक्षा व रोजगार के बीच असंतुलन गंभीर समस्या है ।शिक्षा संस्थानों की संख्या बढ़ने से राज्य में शिक्षित युवाओं की संख्या तो बढ़ती है लेकिन शिक्षित युवाओं के लिए रोजगार के उतने अवसर नहीं बढ़ते हैं। ऐसे में युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार के लिए प्रयास करना पड़ता है। निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर बहुत है, लाखो करोड़ों लोगों को रोजगार मिला भी हुआ है। निजी क्षेत्र में सीधा सा गणित होता है कि जैसी योग्यता की बाजार में मांग है, वैसी योग्यता है तो युवाओं को बहुत पैसा मिलता है। औसत योग्यता वालों को उतना ही मिलता है जितना औसत योग्यता वालों को मिलना चाहिए।

ऐसा भी नहीं है कि सरकार शिक्षित व श्रमिक वर्ग के लिए कुछ नहीं करती है। सरकार के प्रयास से ही यह तय होता है कि किस पद पर कितना वेतन मिलेगा, कुशल, अकुशल व अधर्कुशल श्रमिक को कम से कम कितना पैसा मिलना चाहिए। इसके बाद भी कई क्षेत्रों में लोगों को तय पैसा भी नहीं मिलता है। निजी क्षेत्र मे बहुत से लोगों को कम वेतन में काम करना पड़ता है क्योंकि उनके पास विकल्प नहीं होता है ।कई क्षेत्र में लोगों से ज्यादा वेतन पर्ची पर हस्ताक्षर करवा कर कम पैसे दिए जाते हैं ।कई जगह सरकार द्वारा घोषित वेतनमान नहीं दिया जाता है। वेतनमान न देना पड़े इसलिए संविदा में काम कराया जाता है।

आदमी चाहे कम वेतन मे काम करे, संविदा में काम करे, उसका शोषण तो होता है तो इसके लिए सरकार को लोग दोषी ठहरा सकते हैं। लेकिन यह भी समझने की जरूरत है कि बेरोजगारों की संख्या बढ़ जाती है, बहुत होती है तो उनकी मांग कम हो जाती है। यानी श्रम सस्ता हो जाता है, यानी ज्यादा पैसा नहीं मिलता है ।भारत में लोगों को काम का ज्यादा पैसा नहीं मिलता है यह एक समस्या है यानी इसे जहां श्रमिकों के नजरिए से देखा जाए तो उनको ज्यादा पैसा न मिलना एक समस्या तो है, लेकिन औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए भारत में श्रम सस्ता होना एक ऐसी विशेषता है कि दूसरे देशों के उद्योगपति यहां कारखाने लगाने आ रहे हैं। यानी भारत मे श्रम सस्ता होने के कारण भारत का औद्योगिक विकास तेजी से हो रहा है ।यानी जितने कल कारखाने देश व राज्यो मे लगेंगे लोगों को आने वाले दिनों में उतना ही रोजगार मिलेगा। श्रमिक अशांति फैलाने वालों को समझने की जरूरत है कि रोजगार सबको तब ही मिलेगा जब देश में उद्योग लगेंगे, उद्योग तब ही किसी देश में लगते हैं जब वहां शांति होती है।

पर्यावरण के लिए गंभीर चेतावनी बनता डिजिटल प्रदूषण

डॉ. सुधीर कुमार

डिजिटल प्रदूषण का एक बहुत बड़ा हिस्सा अभौतिक है। इंटरनेट पर हमारा हर क्लिक, सर्च और क्लाउड स्टोरेज बिजली की भारी खपत करता है, जो अधिकांशत: जीवाश्म ईंधन से आती है और कार्बन उत्सर्जन बढ़ाती है। जब हम प्रदूषण शब्द सुनते हैं, तो हमारे मस्तिष्क में जहरीली धुआं उगलती चिमनियां, प्लास्टिक से पटी नदियां या सड़कों पर लगा कचरे का ढेर उभरता है। ये प्रदूषण के वे रूप हैं जिन्हें हम देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। लेकिन इक्कीसवीं सदी की डिजिटल क्रांति के साथ एक ऐसा अदृश्य जहर हमारे वातावरण और जीवन में घुल चुका है, जिसे हम देख नहीं सकते, सूंघ नहीं सकते, लेकिन वह धीरे-धीरे हमारे पर्यावरण और मानसिक स्वास्थ्य को खोखला कर रहा है। इसे हम डिजिटल प्रदूषण कहते हैं। भारत जैसे देश में, जहां डिजिटल साक्षरता और कनेक्टिविटी चरम पर है और डिजिटल इंडिया का सपना साकार हो रहा है, इस अदृश्य खतरे पर कानून, नीति और जनजागरूकता के नजरिये से चर्चा करना अनिवार्य हो गया है।

लोग डिजिटल प्रदूषण को केवल ह्वाई-वेस्ट्स यानी पुराने मोबाइल, टूटे लैपटॉप या खराब चार्जर तक सीमित मान लेते हैं। बेशक, ई-कचरा एक वैश्विक समस्या है, लेकिन डिजिटल प्रदूषण का एक बहुत बड़ा हिस्सा ह्यअभौतिकह्न है। इंटरनेट पर हमारा हर क्लिक, सर्च और क्लाउड स्टोरेज बिजली की भारी खपत करता है, जो अधिकांशतः जीवाश्म ईंधन से आती है और कार्बन उत्सर्जन बढ़ाती है। जब हम डेटा इस्तेमाल करते हैं, तो हजारों मील दूर स्थित विशाल डेटा सेंटर्स सक्रिय हो जाते हैं, जिन्हें चलाने और ठंडा रखने के लिए अत्यधिक ऊर्जा और पानी की आवश्यकता होती है। अत:, डिजिटल गतिविधियों का सीधा और गहरा प्रभाव हमारे पर्यावरण पर पड़ता है।

डिजिटल प्रदूषण के दो सबसे घातक पहलू डार्क डेटा और डिजिटल फुटप्रिंट हैं। डार्क डेटा वह अनुपयोगी डेटा है जो कंपनियों और व्यक्तियों द्वारा केवल स्टोर किया जाता है, जिसका दुनिया भर के कॉर्पोरेट डेटा में हिस्सा लगभग 52 प्रतिशत है। यह डेटा केंद्रों में व्यर्थ ऊर्जा की खपत करता है। वहीं, हमारा डिजिटल फुटप्रिंट भी उतना ही खतरनाक है; एक स्पैम ईमेल अपने पूरे जीवनचक्र में लगभग 0.3 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करने का जिम्मेदार है। यदि हम दुनियाभर में प्रतिदिन भेजे जाने वाले अरबों स्पैम और अनावश्यक ईमेल की गणना करें, तो यह प्रदूषण का स्तर वैश्विक विमानन उद्योग द्वारा फैलाए जाने वाले कुल उत्सर्जन के बराबर पहुंच जाता है। यह तथ्य हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी एक छोटी-सी डिजिटल लापरवाही धरती के तापमान को बढ़ाने में कितनी बड़ी भूमिका निभा रही है।

भारत में डिजिटल प्रदूषण को सीधे तौर पर परिभाषित करने वाला कोई विशिष्ट या एकल कानून मौजूद नहीं है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम (1986) और समय-समय पर संशोधित ई-कचरा प्रबंधन नियम (2016/2022) इसके केवल भौतिक हिस्से (हार्डवेयर कचरे) को कवर करते हैं। असली चुनौती डेटा केंद्रों से होने वाले ऊर्जा उत्सर्जन और डिजिटल हाइजीन की है, जिसके लिए वर्तमान में स्पष्ट कानूनी दिशानिर्देशों की कमी खलती है।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 (जीवन का अधिकार) की व्याख्या करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कई बार स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार को एक मौलिक अधिकार के रूप में स्थापित किया है। यद्यपि ये मामले पारंपरिक औद्योगिक प्रदूषण से संबंधित थे, लेकिन इनमें स्थापित प्रदूषण फैलाने वाला भुगतान करेगा और एहतियाती सिद्धांत का दर्शन डिजिटल दुनिया की बड़ी टेक कंपनियों पर भी समान रूप से लागू होना चाहिए। जो कंपनियां विशाल डेटा सेंटर चलाती हैं और करोड़ों भारतीयों का डेटा प्रोसेस करती हैं, वे डेटा की सुरक्षा के साथ-साथ अपनी पर्यावरणीय जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ सकतीं।

भारत सरकार द्वारा राइट टू रिपेयर पोर्टल का शुभारंभ एक क्रांतिकारी पहल है। कानूनी और नीतिगत रूप से यह उपभोक्ताओं को सशक्त बनाता है कि वे अपने गैजेट्स को कंपनियों के एकाधिकार से बाहर निकालकर ठीक करा सकें। यह पहल न केवल कंपनियों की प्लांड ऑब्सिसलेंस (गैजेट्स को जानबूझकर ऐसा बनाना कि वे जल्दी खराब हो जाएं) की नीति पर लगाम लगाएगी, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक कचरे को कम करने में भी मील का पत्थर साबित होगी। जब कोई उपकरण लंबा चलेगा, तो उसके निर्माण में लगने वाली ऊर्जा और उसके कचरे से होने वाले प्रदूषण में स्वतः कमी आएगी।

केवल कानून और अदालती आदेश डिजिटल प्रदूषण का पूर्ण समाधान नहीं हैं; इसके लिए डिजिटल स्वच्छता को जीवनशैली बनाना अनिवार्य है। शुरुआत इनबॉक्स की सफाई, अनावश्यक न्यूजलेटर्स को अनसब्सक्राइब करने और क्लाउड स्टोरेज से धुंधली तस्वीरों व पुराने बैकअप को हटाकर की जा सकती है। इसके साथ ही, वीडियो स्ट्रीमिंग के दौरान अति-उच्च परिभाषा के बजाय सामान्य स्पष्टता का चुनाव करना डेटा केंद्रों पर दबाव और बिजली की खपत को कम करता है। यह डिजिटल क्लीन-अप न केवल डेटा व्यवस्थित करता है, बल्कि ऊर्जा की बचत कर पर्यावरण संरक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

अब सरकार को ग्रीन डेटा कानूनों के माध्यम से टेक कंपनियों को अक्षय ऊर्जा (सौर, पवन) अपनाने और डेटा केंद्रों की ऊर्जा दक्षता बढ़ाने के लिए जवाबदेह बनाना होगा। हमें समझना होगा कि डेटा भले ही आभासी हो, पर उसे चलाने वाली ऊर्जा भौतिक है, जो धरती को प्रभावित करती है। आज समय की मांग है कि हम ह्वडिजिटल डिटॉक्स के साथ-साथ ह्वडिजिटल क्लीन-अप को अपनाएं।

लेखक कुरुक्षेत्र विवि. के विधि विभाग में सहायक प्रोफेसर है।

बाबू रेवा राम संस्कृत के बड़े कवि- आचार्य महेश चंद्र

डॉ .शर्मा की पुस्तक "छत्तीसगढ़ में संस्कृत" पर रतनपुर में हुई परिचर्चा

नई दृष्टिबिंदु / भिलाई

"यूनेस्को ने श्रीमद्भगवद्गीता और भरत मुनि के नाट्यशास्त्र को विश्व धरोहर घोषित किया है। इधर राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 में भारतीय ज्ञान परम्परा की पूरे देश में धूम है। संस्कृत, शिक्षा नीति की आत्मा है। भारत को सांस्कृतिक दिग्विजय भी इसी ने दिलाई। भारत और भारत के बाहर ब्राह्मणेतर विद्वानों ने भी संस्कृत को विश्व भाषा बनाया। इसी क्रम में रतनपुर में सन् 1812 को जन्मे संस्कृत महाकवि बाबू रेवा राम जी आते हैं।" ये विचार हैं भिलाई के साहित्य-संस्कृति सेवी आचार्य डॉ.महेश चन्द्र शर्मा के। डॉ.शर्मा रतनपुर (बिलासपुर) के साहित्य प्रेमियों के बीच अपनी लोकप्रिय पुस्तक "छत्तीसगढ़ में संस्कृत" पर परिचर्चा में सम्बोधन दे रहे थे।

कुछ वर्ष पूर्व यू.जी.सी.ने डॉ. शर्मा को उक्त विषय पर मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट स्वीकृत किया था। शोध कार्य पूर्ण होने पर वह संस्कृति विभाग, छत्तीसगढ़ शासन के सहयोग से पुस्तक रूप में प्रकाशित हुआ। इस पुस्तक के तीसरे अध्याय में बाबू रेवा राम पर विस्तृत सामग्री है। इसी कृति पर महामाया, महासरस्वती और महालक्ष्मी की ऐतिहासिक नगरी रतनपुर में पं.बलराम प्रसाद पांडेय और पं.श्याम सुन्दर तिवारी आदि ने महत्त्वपूर्ण विचार रखे। उपस्थित कुछ नगरवासी महाकवि रेवाराम के शिष्य भी रहे।

आचार्य डॉ. शर्मा ने बताया कि बाबूजी ने गीत माधवम , सार रामायण दीपिका, ब्राह्मण स्तोत्रम , गंगालहरी और नर्मदा लहरी के साथ हिन्दी में भी अनेक काव्य पुस्तकें रचीं। वे अनेक भाषाओं और संगीत के भी अच्छे जानकार थे। डॉ.शर्मा साहित्यकारों के साथ बाबू हाट भी गये जहाँ बैठ कर बाबू रेवा राम जी लोगों से साहित्य - संस्कृति पर संवाद किया करते थे।

आचार्य पाण्डेय ने आचार्य डॉ.शर्मा को अपनी पुस्तकें श्री विष्णु महायज्ञ स्मारक ग्रन्थ एवं चतुर्युगी नगरी रतनपुर धाम भी भेंट कीं। परिचर्चा में अन्ततः यह भी निष्कर्ष निकला कि जब देश-दुनिया में संस्कृत की धूम है, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और कर्नाटक में कई संस्कृतभाषी गाँव हैं, स्कूलों और खेल मैदानों में हजारों लोगों में संस्कृत बोली जाती है तो, क्यों न हम जनगणना के समय विवरण में लिखें कि हम संस्कृत भाषा को जानते और मानते हैं, ये हमारी मूल भाषा है।

रतनपुर की "बाबू हाट" में आचार्य पं. बलराम प्रसाद पाण्डेय के साथ आचार्य डॉ.महेशचन्द्र शर्मा, जहाँ कभी रेवा राम जी बैठते थे

थमी सुरों की आशा, फिर भी सदा गूंजते रहेंगे हृदयस्पर्शी गीत

हृदयाघात के चलते करोड़ों संगीत प्रेमियों को भले ही आशा भोसले अलविदा कह गई हों लेकिन विविधता लिए सुरीले गीत सदियों तक संगीत प्रेमियों के दिल-दिमाग में गूंजते रहेंगे।8 सितंबर 1933 को जन्मीं आशा भोसले नब्बे साल तक लगातार गाती रहीं। आशा के सुरीले गीतों ने देश-दुनिया के करोड़ों दिलों को छुआ। उनकी कर्णप्रिय धुनों वाले गीतों में जीवन का एक उल्लास रहा है। तभी नब्बेवें जन्मदिन पर लगातार तीन घंटे संगीत कार्यक्रम प्रस्तुत करके वे नया रिकॉर्ड दर्ज कर गईं। जीवनपर्यंत गाने का संकल्प करने वाली आशा ने हिंदी समेत तमाम भारतीय भाषाओं के गीत गाए।

व्यक्तित्व की जीवटता उनके गीतों में भी शिद्दत से मौजूद रही। व्यवहार में मुखरता, गीतों में मस्ती और बेबाक हाजिरजवाबी उनका विशिष्ट गुण था। एक संगीत साधक परिवार में जन्मी आशा ने छोटी उम्र से गाना शुरू किया और अपने गायन में विविधता को लगातार विस्तार दिया। यह विश्वास कर पाना कठिन है कि एक गायिका क्लासिक गीतों से लेकर पॉप, जैज, गजल तथा कव्वाली गाने में भी पारंगत हो सकती है। निस्संदेह, बॉलीवुड व गायकी की दुनिया, उनकी जिंदादिली व गायकी के उल्लासमय अंदाज को सदैव याद रखेगी।

अच्छे गीतकार, सधे संगीतकारों के गीत को अपने खास अंदाज से वे बेहतरीन व कालजयी बना देती थीं। इस तरह मोहम्मद रफी, मुकेश व किशोर कुमार के क्रम में आशाजी का जाना भारतीय गीतमाला के एक युग का अवसान भी है। लेकिन इस महान प्लेबैक सिंगर की आवाज सालों-साल तक भारतीय परिदृश्य में गूंजती रहेगी।

आशा के गीतों की विशिष्टता यह भी है कि पीढ़ियों के बदलाव के बीच भी उनकी जवां आवाज हमेशा पसंद की जाती रही। लेकिन एक हकीकत यह भी है कि हमने उनके चुलबुले गीतों व शोखी के अंदाज को तो देखा, लेकिन उनके जीवन के विकट संघर्ष को नजरअंदाज किया। उन्होंने अपने संगीत की विरासत वाले परिवार में लता मंगेशकर जैसे विराट वट वृक्ष तले अपना विकास किया।

सफलता के पहले पायदान पर पहुंचने का उनका सपना प्रतिभा के बावजूद सफल न हो सका। लता के वर्चस्व के चलते कई प्रतिभाएं समय से पहले ही गुमनामी की दुनिया में चली गईं, लेकिन इसके बावजूद आशा ने अपनी एक अलग पहचान बनाये रखी। उसमें उनकी प्रतिभा के साथ जीवटता भी शामिल रही। उन्होंने पिता दीनानाथ मंगेशकर की संगीत विरासत को समृद्ध ही किया। 'चुनरिया' फिल्म से पार्श्व गायन की शुरुआत करने वाली आशा ने फिर मुड़कर नहीं देखा। वे लता के एकछत्र राज्य के बावजूद कई संगीतकारों की पहली पसंद बनी।

उन्हें उस दौर के बड़े संगीतकारों व बड़े बैनरों के साथ काम करने के भी अवसर मिले, बावजूद इसके कि मैदान में लता के अलावा कई अन्य प्रतिस्पर्धी मौजूद थे। उनकी निजी जिंदगी का संघर्ष भी साथ-साथ चला। निजी फैसलों ने भी मंगेशकर परिवार में असहज स्थिति पैदा की। इससे उनके कैरियर की गति बाधित हुई। कालांतर बूट पॉलिश व परिणीता के गीतों की सफलता के बाद ओपी नैयर के सान्निध्य में उनके कैरियर को नई दिशा मिली। उनकी कामयाबी से देश परिचित है। उनके जाने से पैदा हुआ शून्य सदैव अखरता रहेगा।

कच्ची पर्ची व्यवस्था पर रोक से किसानों को मिलेगा न्याय

डॉ. विरेन्द्र सिंह

हाईकोर्ट के फैसले के बाद सरकार ने कृषि उपज मंडियों के आढ़तियों को अवैध कच्ची पर्ची व्यवस्था तुरंत बंद करने और कानूनन जे-फार्म अनिवार्य रूप से किसानों को देने का आदेश दिया है। यह महत्वपूर्ण कृषि विपणन सुधार है।

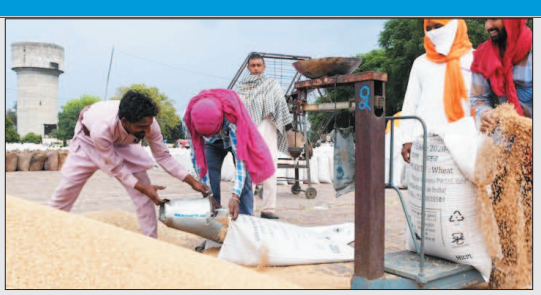

भारत में कृषि विपणन का एक व्यवस्थित ढांचा मौजूद था, जो ग्रामीण आत्मनिर्भरता और स्थानीय मंडियों पर आधारित था। किसान न केवल अपने उपभोग के लिए, बल्कि विशेष फसलों जैसे कपास, मसाले, अनाज आदि का उत्पादन व्यापार के लिए भी करते थे। यह विपणन व्यवस्था ग्राम आधारित थी। किसान अपने उत्पादन के साधनों के स्वामी होते थे और स्वतंत्र रूप से अपनी फसल को बाजार में बेचने का निर्णय ले सकते थे।

देश की आजादी के बाद, सर छोटूराम द्वारा ब्रिटिश पंजाब में लागू किए गए कृषि उपज मंडी सुधारों के आधार पर कृषि नीति तैयार की गई और राज्यों ने कृषि उपज विपणन समिति अधिनियम पारित किए, जिसके तहत स्थानीय मंडियां स्थापित की गईं। इसका उद्देश्य बिचौलियों के शोषण को कम करना और किसानों को उचित मूल्य दिलाना था। शुरुआत में, कृषि एवं कृषि प्रबंधन समितियां वास्तव में प्रभावी थीं। इन्होंने कृषि व्यापार में नीलामी आधारित मूल्य निर्धारण, मानकीकृत वजन प्रणाली, लाइसेंस प्राप्त व्यापारियों और विनियमित लेन-देन प्रक्रियाओं को लागू किया। इनके गठन के समय, एपीएमसी को नीलामी के माध्यम से बेहतर मूल्य सुनिश्चित करने और किसानों को विपणन की उच्च लागत और उपज के नुकसान से बचाने के लिए एक लोकतांत्रिक समाधान के रूप में सराहा गया था।

समय के साथ, किसानों की सुरक्षा के लिए बनाई गई व्यवस्थाएं ही उनके विरुद्ध कार्य करने लगीं। एक पारदर्शी मूल्य निर्धारण प्रणाली ऐसी प्रणाली में परिवर्तित हो गई जहां कीमतें व्यापारियों और कमीशन एजेंटों द्वारा साज-बाज द्वारा तय की जाने लगी। दशकों से कई संरचनात्मक विकृतियां संचित होती रहीं।

भारत की कृषि को जटिल आपूर्ति श्रृंखलाओं से लगातार चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिनमें कई बिचौलिए शामिल हैं। साथ ही, प्रतिबंधात्मक घरेलू विपणन नीतियां और सीमा संबंधी उपाय भी हैं, जिनके कारण समीक्षाधीन अवधि के अधिकांश समय में कीमतें औसतन अंतर्राष्ट्रीय बाजार स्तर से नीचे रही हैं। इसके साथ ही, कई वस्तुओं में अंतिम उपभोक्ता मूल्य में किसानों का हिस्सा बेहद कम बना हुआ है।

हालांकि, सीएसीपी ने 23 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की सिफारिश की थी, लेकिन प्रभावी खरीद मुख्य रूप से एफसीआई के माध्यम से चावल और गेहूं के लिए ही संचालित होती थी, जो धान की कुल बिक्री का केवल एक-चौथाई और गेहूं का 20 प्रतिशत ही एमएसपी पर बेचा गया। दशकों की नीति के बावजूद, अधिकांश किसान गारंटीकृत न्यूनतम मूल्य प्राप्त नहीं कर सके। दालों या तिलहन की खेती करने वाले किसानों के लिए, एमएसपी अक्सर एक घोषणा मात्र रह जाती थी, जिसके पीछे कोई खरीद तंत्र नहीं होता था।

खाद्यान्न जांच समिति की सिफारिशों के बाद, सरकार ने 1950 के दशक के उत्तरार्ध में खाद्यान्नों में सरकारी व्यापार भी शुरू किया। इसके तहत सरकार ने किसानों को उचित मुआवजा सुनिश्चित करने के लिए गेहूं और चावल जैसी प्रमुख वस्तुओं की पूर्व निर्धारित कीमतों पर खरीद की। वर्ष 1961 में पंजाब राज्य कृषि उपज मंडी अधिनियम पारित हुआ, जिसकी नियमावली पंजाब राज्य कृषि उपज मंडी अधिनियम रूल्स-1962 के अन्तर्गत लागू की गई। इस अधिनियम की सेक्शन-43, रूल 24 (11, 12 और 14) के अनुसार आढ़तियों को कृषि उपज बिक्री-तुलाई के तुरंत बाद किसानों को भुगतान और जे-फार्म जारी करना कानूनन अनिवार्य है। लेकिन मंडियों में इन नियमों का खुला उल्लंघन करते हुए, फसल उपज की सरकारी खरीद में कार्टेल बनाकर और अवैध कच्ची पर्ची (अनौपचारिक रसीद) व्यवस्था द्वारा समर्थन मूल्य से कम पर कृषि उपज खरीदने से किसानों का खुला शोषण हो रहा था। आढ़तियों की अवैध कच्ची पर्ची व्यवस्था से किसानों का आर्थिक नुकसान हो रहा है।

कच्ची पर्ची व्यवस्था से किसानों के लगातार हो रहे शोषण के खिलाफ लेखक द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए, हाईकोर्ट ने 27 जनवरी, 2026 को सरकार को अवैध कच्ची पर्ची व्यवस्था पर रोक लगाने के दिशानिर्देश जारी किए। हरियाणा सरकार द्वारा अनुपालना करते हुए 1 अप्रैल को प्रदेश की कृषि उपज मंडियों के आढ़तियों को अवैध कच्ची पर्ची व्यवस्था तुरंत बंद करने और कृषि उपज बिक्री-तुलाई के तुरंत बाद कानूनन जे-फार्म अनिवार्य रूप से किसानों को देने के आदेश जारी किए गए। सरकार द्वारा कच्ची रसीद (पर्ची) व्यापार पर प्रतिबंध लगाए जाने से मंडियों में दस हजार करोड़ रुपये वार्षिक से अधिक के किसानों के शोषण और सरकारी धन के घोटालों पर भी लगाम लग सकेगी।

अधूरे अंडरब्रिज निर्माण का काम जल्द करो पूरा नहीं तो होगा 7 दिवस पर उग्र आंदोलन -कांग्रेस

वरिष्ठ पार्षद हफीज खान व आसिफ अली के नेतृत्व में मुख्य स्टेशन प्रबंधक को दिया ज्ञापन

नई दृष्टिबिंदु / राजनांदगांव

तीन वर्षों से अधूरा पड़ा अन्डर ब्रिज पटरीपार वासियो के लिए मुसीबत बन चुका है ।इस समस्या पर पुनः रेल्वे प्रशासन का ध्यान आकर्षित कराने के लिए मुख्य स्टेशन प्रबंधक को मंडल अभियंता के नाम से वरिष्ठ पार्षद हाफिज खान एवम कांग्रेस नेता आसिफ अली के नेतृत्व में ज्ञापन दिया गया।

वरिष्ठ पार्षद हाफिज खान ने बताया कि विगत 3 वर्षो से अंडर ब्रिज क्रमांक 459 गौरी नगर और 460 स्टेशन पारा में निर्माण कार्य अधूरा है जिसके कारण लोगो को आवाजाही में दिक्कत का सामना

करना पड़ रहा। निर्माण कार्य अधूरा होने से उक्त स्थल पर कई बार गम्भीर दुर्घटना भी घट चुकी है।

कांग्रेस नेता आसिफ अली ने कहा कि पूर्व में भी रेल्वे प्रशासन को ज्ञापन के माध्यम से अंडर ब्रिज का निर्माण कार्य पूर्ण कराने के लिए अवगत कराया जाता रहा है किन्तु आश्वासन के बाद भी रेल्वे का उदासीन रवैया अब भी जारी है। उन्होंने रेल्वे प्रशासन को चेतवानी दी है यदि 7 दिवस के भीतर निर्माण कार्य शुरू नही हुआ तो पटरीपार के रहवासी रेल्वे स्टेशन में उग्र प्रदर्शन और रेल रोको जैसी कार्यवाही भी करेंगे जिसकी समस्त जवाबदारी रेल्वे प्रशासन की होगी ।

ज्ञापन देने में मुख्य रूप से वार्ड पार्षद छोटेलाल रामटेके, पूर्व पार्षद समद खान, अब्बास खान, मंडल अध्यक्ष कृष्णा मेश्राम, चंचल देवांगन, विजय यादव, जाकिर खान, ताहिर खान, गोपाल सिन्हा, शेख अनीश , पीटर मारियो, हरीश यादव, रॉबिन जान, जितेंद्र साहू उपस्थित थे।

खास खबर

ग्रामीणों को बड़ी राहत, सोमनी स्वास्थ्य केंद्र को मिली 108 एम्बुलेंस

नई दृष्टिबिंदु / राजनांदगांव

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सोमनी में अब आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाएं और तेज हो जाएंगी। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह एवं राजनांदगांव सांसद संतोष पाण्डेय के प्रयासों से केंद्र को 108 एम्बुलेंस की सुविधा मिली है। यह एम्बुलेंस मुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री द्वारा प्रदान की गई है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के मरीजों को समय पर इलाज मिल सकेगा। भाजपा ग्रामीण मंडल के पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं एवं अस्पताल स्टाफ की उपस्थिति में एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया गया। इस मौके पर सहकारिता प्रकोष्ठ के मीडिया प्रभारी कृष्णा तिवारी, सोमनी की सरपंच नीलिमा साहू सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे।

इस नई सुविधा से आसपास के गांवों के लोगों को आपात स्थिति में तत्काल अस्पताल पहुंचाने में बड़ी मदद मिलेगी। अब गंभीर मरीजों को लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, जिससे इलाज में देरी की समस्या काफी हद तक कम होगी। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं ने क्षेत्र के विकास और स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए जनप्रतिनिधियों का आभार व्यक्त किया। ग्रामीणों ने भी इस पहल को राहत भरा कदम बताते हुए उम्मीद जताई कि इससे स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच और बेहतर होगी।

कलेक्टर ने की लोगों से अपील - नागरिक निभाएं अपनी जिम्मेदारी, दें सही जानकारी

बेमेतरा। जिले में आगामी जनगणना कार्य को सुव्यवस्थित और सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए प्रशासन द्वारा व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। कलेक्टर प्रतिष्ठा ममगाई ने जनगणना से जुड़े सभी आवश्यक व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए इसे एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्य बताया और नागरिकों से इसमें सक्रिय सहभागिता की अपील की।

कलेक्टर ने जानकारी दी कि जिले के सभी विकासखंडों में जनगणना कार्य को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है। इस प्रशिक्षण में प्रगणकों को घर-घर जाकर जानकारी संकलन की प्रक्रिया, नागरिकों से संवाद के तरीके, डेटा की सटीकता बनाए रखने तथा आवश्यक सावधानियों के बारे में विस्तार से बताया गया है।

कलेक्टर ने कहा कि जनगणना केवल जनसंख्या की गणना नहीं है, बल्कि यह देश और राज्य के समग्र विकास की आधारशिला है। जनगणना से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर ही शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आवास और आधारभूत संरचना से जुड़ी योजनाएं तैयार की जाती हैं। इसलिए नागरिकों द्वारा दी गई जानकारी की सटीकता अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब जनगणना प्रगणक उनके घर पहुंचे, तो वे परिवार के सभी सदस्यों, उनकी शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य आवश्यक विवरणों की सही जानकारी उपलब्ध कराएं। नागरिक किसी भी प्रकार के भ्रम में न आएं और जनगणना कार्य में पूर्ण सहयोग प्रदान करें। प्रशासन द्वारा स्पष्ट किया गया है कि जनगणना के दौरान एकत्रित की गई सभी व्यक्तिगत जानकारी पूरी तरह गोपनीय रखी जाती है। इसका उपयोग केवल सांख्यिकीय उद्देश्यों के लिए किया जाता है और किसी भी प्रकार से इसका दुरुपयोग नहीं किया जाता। कलेक्टर प्रतिष्ठा ममगाई ने अंत में कहा कि जनगणना कार्य में सक्रिय भागीदारी निभाकर नागरिक राष्ट्र के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।उन्होंने सभी से जिम्मेदारीपूर्वक सहयोग करने और सटीक जानकारी साझा करने की अपील की।

क्षेत्र के नागरिकों को मिले सहज स्वास्थ्य सेवा, विभाग संवेदनशीलता से करें कार्य- कलेक्टर

नई दृष्टिबिंदु / बेमेतरा

कलेक्टर प्रतिष्ठा ममगाई ने विभागीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक लेकर विभागीय योजनाओं सेवाओं और कार्यक्रमों की जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन और प्रगति की समीक्षा की। कलेक्टर ने कहा कि सभी अधिकारी आमजनों तक विभागीय योजनाओं और कार्यक्रमों को पहुंचाने और लाभान्वित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी प्रकार की कोताही नहीं करने निर्देशित की है।

कलेक्टर ने बैठक में स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, आवास योजना सहित विकासखंडों में संचालित नरेगा योजना की समीक्षा की। उन्होंने सभी योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन करने निर्देशित किया। कलेक्टर ने बैठक में टीबी (क्षय रोग) उन्मूलन कार्यक्रम की समीक्षा के दौरान अपेक्षित प्रगति में कमी पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि दिए गए निर्देश के आधार पर लक्ष्य में कमी एक गंभीर स्थिति को प्रदर्शित करता है। कलेक्टर ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को स्पष्ट चेतावनी दी है कि टीबी मुक्त भारत अभियान में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार नए मरीजों की पहचान करने और उनके उपचार की समुचित व्यवस्था पर जोर दिया। कलेक्टर ने फील्ड स्टाफ और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को मैदानी सर्वे करने और फॉलो-अप करने निर्देशित किया। लक्ष्यानुरूप परिणाम प्राप्त करने के लिए सार्थक कार्यवाही करने निर्देशित की।

भीषण गर्मी में पेयजल आपूर्ति के लिए रहें सचेत

कलेक्टर ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को पेयजल व्यवस्था दुरुस्त रखने निर्देशित की है। गर्मी के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए कलेक्टर ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अधिकारियों को जिले में निर्बाध पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के कड़े निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि आम जनता को पीने के पानी के लिए किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े।

उन्होंने जिले के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जो भी हैंडपंप खराब हैं, उन्हें 24 से 48 घंटों के भीतर सुधारने कहा है। उन्होंने जल जीवन मिशन के तहत पूर्ण हो चुकी योजनाओं का लाभ हर घर तक पहुँचे, यह सुनिश्चित करने कहा है जाए। जहां भी तकनीकी खराबी है। इसके साथ ही कलेक्टर ने पेयजल संबंधी शिकायतों के निराकरण के लिए जिला स्तर पर एक हेल्पलाइन नंबर या कंट्रोल रूम सक्रिय रखने कहा है। जिससे नागरिक अपनी समस्या सीधे विभाग तक पहुँचा सकें। कलेक्टर ने जिन क्षेत्रों में भू-जल स्तर नीचे गिर रहा है, वहां वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में टैंकरों के माध्यम से जलापूर्ति की योजना तैयार रखने के निर्देश दिए हैं। साथ ही साथ पेयजल की शुद्धता बनाए रखने के लिए समय-समय पर ब्लीचिंग पाउडर और क्लोरीनीकरण की प्रक्रिया सुनिश्चित करने को कहा गया है।

कलेक्टर ने विभाग के कार्यपालन अभियंता को क्षेत्र का दौरा करने और कार्यों की साप्ताहिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।

महत्वाकांक्षी योजनाओं और कार्यक्रमों की समीक्षा

कलेक्टर ने विभागीय महत्वाकांक्षी योजनाओं और कार्यक्रमों की समीक्षा की। जनकल्याणकारी योजनाओं की जमीनी हकीकत की जानकारी लेते हुए आने वाली बाधाओं को दूर करने निर्देशित की। बैठक में महत्वपूर्ण योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। कलेक्टर ने विभागवार समीक्षा करते हुए अपेक्षित प्रगति विशेष जोर दिया। उन्होंने स्वास्थ्य एवं शिक्षा ,स्कूलों और अस्पतालों में बुनियादी सुविधाओं की स्थिति, पेयजल एवं स्वच्छता, ग्रेजल जीवन मिशनश जैसे प्रोजेक्ट्स की वर्तमान स्थिति की समीक्षा की। इसके साथ ही बुनियादी ढांचा, सड़कों, पुलों और सरकारी भवनों के निर्माण की समीक्षा की।

कलेक्टर ने अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कार्यशैली में सुधार लाने के लिए कड़े निर्देश दिए। उन्होंने आगे कहा कि समय सीमा सभी लंबित कार्यों को निर्धारित समय के भीतर पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यों और सेवाओं की गुणवत्ता में किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। कलेक्टर ने अंतर्विभागीय समन्वय के साथ लक्ष्य अर्जित करने कहा। उन्होंने हितग्राहियों का चयन कर योजनाओं का लाभ अंतिम पात्र व्यक्ति तक पहुंचाने कहा।

बिजली बिल भुगतान समाधान योजना से उपभोक्ताओं को राहत, अभियान जारी

नई दृष्टिबिंदु / बेमेतरा

मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना 2026 के तहत दुर्ग रीजन (दुर्ग, बालोद एवं बेमेतरा) में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं किसानों को राहत देने के उद्देश्य से अभियान युद्ध स्तर पर संचालित किया जा रहा है। इस जनकल्याणकारी योजना के अंतर्गत अब तक तीनों जिलों के 48 हजार से अधिक सक्रिय एवं निष्क्रिय उपभोक्ताओं को मूल बकाया राशि एवं अधिभार (सरचार्ज) में कुल 14 करोड़ 90 लाख 43 हजार रुपए की छूट प्रदान की जा चुकी है। योजना का मुख्य उद्देश्य बीपीएल श्रेणी के निम्नदाब घरेलू उपभोक्ताओं एवं कृषि उपभोक्ताओं को आर्थिक संबल प्रदान करना है।

योजना के तहत अब तक 30,414 निष्क्रिय उपभोक्ता लाभान्वित हो चुके हैं, वहीं पात्र 29,886 सक्रिय उपभोक्ताओं में से लगभग 61 प्रतिशत ने पंजीयन पूर्ण कर लिया है, जिससे योजना के प्रति उत्साह स्पष्ट दिखाई दे रहा है। दुर्ग रीजन के 9 विद्युत संभागों में सर्वाधिक लाभ बेमेतरा संभाग (20,879) में मिला है। इसके अलावा साजा (6,221), अहिवारा (4,487), भिलाई पूर्व (4,397), बालोद (3,832), दुर्ग संधारण (2,561), पाटन (2,263), भिलाई पश्चिम (2,111) एवं दुर्ग शहर (1,976) संभागों के उपभोक्ता भी योजना से लाभान्वित हुए हैं। लाभान्वित उपभोक्ताओं द्वारा सक्रियता दिखाते हुए अब तक लगभग 1 करोड़ 45 लाख 42 हजार रुपए की बकाया राशि विभाग में जमा की जा चुकी है।

सीएसपीडीसीएल दुर्ग क्षेत्र के मुख्य अभियंता संजय खंडेलवाल ने बताया कि योजना का लाभ हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए तीनों जिलों के 62 वितरण केंद्रों एवं 12 जोन में विशेष समाधान शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। विभागीय टीमें घर-घर जाकर उपभोक्ताओं को योजना की जानकारी एवं प्रक्रिया से अवगत करा रही हैं। उन्होंने अपील की है कि बीपीएल, एपीएल एवं कृषि श्रेणी के वे उपभोक्ता, जिनके 31 मार्च 2023 के पूर्व के बिजली बिल बकाया हैं, वे अपने नजदीकी वितरण केंद्र या जोन में पहुंचकर इस योजना का लाभ उठाएं। बकाया बिलों का निपटारा कर उपभोक्ता भविष्य में निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित कर सकते हैं तथा बिजली कंपनी के सुदृढ़ीकरण में सहयोग दे सकते हैं।

सब्जी उत्पादन में नवाचार :आधुनिक तकनीक अपनाकर मैना बनीं सफल उद्यानिकी कृषक

नई दृष्टिबिंदु / मोहला

जिले के ग्राम हथरा की निवासी श्रीमति मैना बाई एक मेहनती एवं प्रेरणादायक कृषक हैं। उनकी शैक्षणिक योग्यता भले ही प्राथमिक स्तर तक सीमित रही हो, लेकिन अपने अनुभव, लगन और मेहनत के बल पर उन्होंने कृषि के क्षेत्र में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है।

शुरुआत में श्रीमति मैना बाई पारंपरिक खेती करती थीं। वर्ष 2011-12 में उद्यानिकी विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी मिलने पर उन्होंने नई दिशा में कदम बढ़ाया। प्रारंभ में उन्होंने मसाला एवं सब्जी उत्पादन के लिए केवल 0.250 हेक्टेयर भूमि में खेती शुरू की। जब उन्होंने पारंपरिक फसलों की तुलना में सब्जियों से अधिक उत्पादन और आय देखी, तो उन्होंने साहसिक निर्णय लेते हुए अपनी पूरी 1.011 हेक्टेयर भूमि में सब्जी उत्पादन प्रारंभ कर दिया।

राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अंतर्गत उन्हें विभिन्न योजनाओं का लाभ मिला। वर्ष 2024-25 में जिला खनिज न्यास के सहयोग से उनके खेत में सूक्ष्म सिंचाई (ड्रिप) प्रणाली स्थापित की गई। इसके साथ ही सब्जी उत्पादन को और उन्नत बनाने हेतु मल्चिंग शीट और शेडनेट की सुविधा भी प्रदान की गई।

वर्तमान वर्ष 2025-26 में उन्होंने जनवरी एवं फरवरी माह में करेला, बैंगन एवं टमाटर की खेती की। आधुनिक तकनीकों के उपयोग से उनकी खेती की लागत में कमी आई और उत्पादन में वृद्धि हुई। जहां उनकी कुल लागत लगभग 1.25 लाख रुपए रही, वहीं अनुमानित आय लगभग 3.00 लाख रुपए तक पहुंच गई।

आज श्रीमति मैना बाई अपने क्षेत्र में एक सफल उद्यानिकी महिला कृषक के रूप में जानी जाती हैं। उनकी सफलता न केवल उनके परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत बना रही है, बल्कि अन्य किसानों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत है। उनका यह प्रयास दर्शाता है कि सही मार्गदर्शन, आधुनिक तकनीक और मेहनत के बल पर कोई भी किसान उन्नति की नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकता है।

नक्सल क्षेत्र में विकास की दस्तक–विषम परिस्थितियों में सुखदेव को मिला अपना आशियाना

मोहला। विषम परिस्थितियों में जीवन जी रहे ग्राम पंचायत मरकेली के निवासी सुखदेव निषाद के जीवन में अब एक नई सुबह आई है। दूरस्थ और नक्सल प्रभावित क्षेत्र में रहने वाले सुखदेव का जीवन लंबे समय तक कठिनाइयों, असुरक्षा और संसाधनों की कमी से जूझता रहा। सीमित आय, जर्जर कच्चा मकान और परिवार की सुरक्षा की चिंता उनके दैनिक जीवन का हिस्सा बन चुकी थी। सुखदेव निषाद की पत्नी श्रीमती जानकी बाई निषाद बताती हैं कि उनके पति गांव में मजदूरी और कृषि कार्य कर परिवार का भरण-पोषण करते हैं। वर्षों तक उनका परिवार मिट्टी और खपरैल से बने जर्जर घर में रहने को मजबूर था, जहां हर मौसम एक नई चुनौती लेकर आता था। विशेषकर बारिश के दिनों में घर में पानी भर जाना, दीवारों में सीलन और बच्चों की पढ़ाई में बाधाएं आम बात थीं। ऐसे कठिन समय में शासन की पहल ने उनके जीवन को नई दिशा दी। वर्ष 2024-25 में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत सुखदेव निषाद का चयन हुआ और उन्हें पक्का मकान स्वीकृत हुआ। आज उनका परिवार एक सुरक्षित, मजबूत और सम्मानजनक आवास में रह रहा है।

नेशनल लोक अदालत 9 मई को, प्रकरणों के निराकरण के लिए प्रचार-प्रसार करें तेज-न्यायाधीश

नई दृष्टिबिंदु / बेमेतरा

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बेमेतरा द्वारा आगामी नेशनल लोक अदालत 09 मई 2026 के सफल आयोजन एवं अधिक से अधिक प्रकरणों के निराकरण के उद्देश्य से व्यापक प्रचार-प्रसार किए जाने के संबंध में बैठक आयोजित की गई। बैठक का आयोजन श्रीमती सरोज नंद दास, प्रधान जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बेमेतरा के मार्गदर्शन में एवं श्रीमती स्वर्णप्रभा यादव, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बेमेतरा की उपस्थिति में किया गया।

इस दौरान जानकारी दी गई कि नेशनल लोक अदालत के माध्यम से विभिन्न प्रकार के मामलों जैसे बैंक वसूली प्रकरण, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण, वैवाहिक/पारिवारिक विवाद,

श्रम विवाद, राजस्व प्रकरण, चेक बाउंस मामले, विद्युत एवं जल कर से संबंधित प्रकरणों सहित अन्य सिविल व आपराधिक मामलों का आपसी सहमति से निराकरण किया जाएगा। बैठक में बताया गया कि लोक अदालत में निराकृत प्रकरणों में पक्षकारों को न्यायालय शुल्क की वापसी की जाती है तथा निर्णय के विरुद्ध कोई अपील भी नहीं होती, जिससे समय एवं धन दोनों की बचत होती है।

निःशुल्क विधिक सहायता एवं सलाह हेतु छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर के टोल फ्री नंबर 15100 तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बेमेतरा के दूरभाष नंबर 07824-299152 पर संपर्क किया जा सकता है। आगामी नेशनल लोक अदालत के सफल आयोजन हेतु पैरालीगल वॉलेंटियर्स के माध्यम से व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाया जाएगा तथा चौक-चौराहों पर होर्डिंग, फ्लेक्स एवं पंपलेट्स के जरिए अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार किए जाने के निर्देश दिए ।

बेमेतरा में भूमि अर्जन प्रक्रिया के चलते प्रभावित क्षेत्रों में निर्माण कार्यों पर रोक

कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), जिला बेमेतरा द्वारा दुर्ग पश्चिम अंतर्गत सड़क संपर्क योजना के तहत प्रस्तावित बायपास-टू-नवागढ़-मुंगेली - लोरमी कोटा-रतनपुर मार्ग के निर्माण हेतु भूमि अर्जन प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। इस परियोजना के अंतर्गत मार्ग चौड़ीकरण के लिए 25 मीटर चौड़ाई में भूमि की आवश्यकता निर्धारित की गई है। इस संबंध में जारी आदेश के अनुसार, तहसील बेमेतरा के ग्राम सांवतवपुर, निनवा, डूंडा, हथमुड़ी, कंतेली, सिंघौरी, गस्ती चौक नयापारा एवं बेमेतरा सिग्नल चौक तथा बेमेतरा नगर के वार्ड क्रमांक 11, 12, 13, 14, 16 एवं 17 सहित तहसील बेरला के ग्राम देवरबीजा, हड़गांव, भेड़नी, केछवई आदि क्षेत्रों में प्रस्तावित सड़क किनारे स्थित भूमि प्रभावित होगी। प्रशासन द्वारा स्पष्ट किया गया है कि इन क्षेत्रों में भूमि अर्जन की कार्यवाही प्रारंभिक प्रकाशन के चरण में है और समस्त राजपत्र गतिविधियों की प्रक्रिया जारी है। इसी क्रम में, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के पालन में संबंधित क्षेत्रों में आगामी आदेश तक क्रय-विक्रय, नामांतरण, बंटवारा, निजी निर्माण कार्य एवं अन्य लेन-देन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। जिला प्रशासन ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए तथा किसी भी प्रकार के उल्लंघन पर आवश्यक कार्रवाई की जाए।

प्रशासन की अपील : जिला प्रशासन ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे जारी निर्देशों का पालन करें और किसी भी प्रकार के भूमि संबंधी लेन-देन या निर्माण कार्य से पूर्व संबंधित विभाग से जानकारी अवश्य प्राप्त करें।

विनय पाठक ने बताया 'एवरीबडी लव्स सोहराब हांडा' का अनुभव

मनोरंजन की दुनिया में कई बार ऐसी फिल्में आती हैं, जो कलाकारों के बीच की असली दोस्ती और तालमेल की वजह से खास बन जाती हैं। ऐसी ही एक फिल्म इन दिनों चर्चा में है, जिसका नाम है 'एवरीबडी लव्स सोहराब हांडा'। इस फिल्म को दर्शकों की ओर से शानदार प्रतिक्रिया मिल रही है। फिल्म के प्रमोशन के दौरान अभिनेता विनय पाठक ने अपने अनुभव साझा किए। विनय पाठक ने कहा, ''मेरे और मेरे करीबी दोस्तों रणवीर शौरी और रजत कपूर के बीच एक खास चीज है, जो हमें हमेशा जोड़कर रखती है, और वह है खाने को लेकर प्यार। जब हम तीनों साथ बैठते हैं, तो हमारे लिए खाना ही सबसे बड़ा 'सिनेमा' बन जाता है। हम कैमरे या शूटिंग की चिंता नहीं करते, बल्कि खाने और बातचीत का पूरा आनंद लेते हैं। मैं शाकाहारी हूं, जबकि मेरे दोस्त नॉन-वेजिटेरियन हैं। इसके बावजूद, खाने के प्रति हमारा जुनून एक समान है। चाहे कहीं भी जाएं या किसी भी स्थिति में हों, खाने के लिए उनका प्यार कभी कम नहीं हुआ। यही छोटी-छोटी चीजें हमारी दोस्ती को मजबूत बनाती हैं, हमें एक-दूसरे के करीब लाती हैं।'' जब विनय पाठक से उनकी फिल्म में निभाए गए किरदार के बारे में पूछा, तो उन्होंने कहा, ''यह कहना सही नहीं होगा कि फिल्म पूरी तरह मेरे किरदार पर टिकी है। कोई भी अच्छी फिल्म सिर्फ एक कलाकार के दम पर नहीं चलती, बल्कि यह सभी के मिलकर किए गए काम का नतीजा होती है।'' उन्होंने फिल्म की असली ताकत के बारे में बात करते हुए कहा, ''इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी शानदार कहानी और बेहतरीन डायलॉग्स हैं। निर्देशक रजत कपूर ने फिल्म के हर पहलू को बहुत संतुलित तरीके से संभाला है। वह सुनिश्चित करते हैं कि हर कलाकार को अपनी जगह मिले और सभी मिलकर एक मजबूत कहानी पेश करें। विनय पाठक ने कहा, ''इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत यही है कि इसमें सभी कलाकार मिलकर काम कर रहे हैं। जब सभी किरदार एक साथ आते हैं, तो वे एक मजबूत यूनिट बन जाते हैं, जो दर्शकों को शुरू से अंत तक बांधे रखती है।''

आत्मविश्वास से बड़ा कोई स्टाइल नहीं: अनुपम खेर

बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता अनुपम खेर ने अपनी पुरानी यादों को साझा करते हुए इंस्टाग्राम पर एक प्रेरणादायक पोस्ट किया। इस पोस्ट पर उन्होंने बताया कि शुरुआती दिनों में कम बालों की वजह से वे काफी शर्माते थे और टोपी पहनकर खुद को छुपाते थे। अभिनेता ने अपने इंस्टाग्राम पर पुरानी और कुछ नई तस्वीरें पोस्ट कीं। इस पोस्ट में उन्होंने लिखा कि आत्मविश्वास ही सबसे अच्छा हेयरस्टाइल है। अनुपम ने लिखा, 'गंजापन हमेशा खूबसूरत होता है। अभिनेता ने पुराने दिनों को याद करते हुए लिखा, 'एक समय था, जब मैं मुंबई आया था। आंखों में बड़े सपने थे, लेकिन सिर पर बाल बहुत कम थे। उस वक्त गंजा होना और एक्टर बनने का सपना देखना कोई फैशन नहीं माना जाता था। इसलिए मैं अक्सर टोपी पहनकर खुद को छुपाता था। यह स्टाइल के लिए नहीं, बल्कि अपनी झिझक की वजह से करता था। अभिनेता ने बताया कि कुछ साल बाद उन्हें एक अहम बात समझ में आई। उन्होंने लिखा, 'मुझे एहसास हुआ कि आत्मविश्वास ही सबसे बड़ी पुंजी है। इसलिए मैंने वो टोपी सिर्फ सिर से नहीं, बल्कि अपने मन से भी उतार दी। अभिनेता ने गर्व करते हुए लिखा, 'अब गंजापन बोल्ड, खूबसूरत और फैशन बन गया है। लोग वही लुक अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे मैं पहले छुपाता था। जिंदगी का अपना ही मजेदार अंदाज होता है। जय हो। अनुपम खेर ने अपने करियर में हमेशा अलग-अलग भूमिकाओं से सबको प्रभावित किया है। उन्होंने शुरुआती संघर्ष के बावजूद उन्होंने कभी अपना लुक बदलने की कोशिश नहीं की। अभिनेता इन दिनों 2006 की फिल्म 'खोसला का घोसला' के दूसरे भाग में अपने प्यारे किरदार कमल किशोर खोसला की भूमिका निभाते नजर आएंगे। दिबाकर बनर्जी द्वारा निर्देशित इस सीक्वल में बोमन ईरानी, ??परवीन डबास, रणवीर शौरी, किरण जुनेजा और तारा शर्मा के साथ-साथ रवि किशन जैसे कुछ नए चेहरे भी नजर आएंगे। इसके अलावा, खेर ने एक और रोमांचक प्रोजेक्ट के लिए मशहूर निर्देशक सूरज बड़जात्या के साथ भी हाथ मिलाया है।

है जवानी तो इश्क होना है: गिफ्ट पुराना लेकिन पैकेजिंग नई, क्या गोविंदा को बीट कर पाएंगे वरुण धवन

वरुण धवन, मृणाल ठाकुर और पूजा हेगड़े स्टारर फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' का पहला लुक रिलीज हो गया है। पहले लुक से फिल्म की कहानी साफ है कि पुराने गिफ्ट को नई पैकिंग के साथ सिनेमाधरों में उतारा जा रहा है। फिल्म में वरुण धवन, मृणाल ठाकुर और पूजा हेगड़े तीनों के बीच बेहतरीन केमिस्ट्री दिखाई गई है लेकिन फिल्म को लेकर सारा सस्पेंस पहले लुक में खुलकर सामने आ चुका है। 'है जवानी तो इश्क होना है' में वरुण धवन एक साथ दो-दो पत्नियों के साथ दोहरी जिंदगी जीने वाले हैं। पहली पत्नी है मृणाल ठाकुर और दूसरी हैं पूजा हेगड़े। पहले लुक को देखकर आपको गोविंदा की फिल्म 'सैंडविच' और 'साजन चले ससुराल' की याद आ जाएगी। कुल मिलाकर सलमान खान के गाने के टाइटल और गोविंदा की फिल्म की स्क्रिप्ट का मिक्स कॉकटेल दर्शकों को देखने को मिल सकता है। गोविंदा की फिल्म सैंडविच सभी को याद होगी, जिसमें महिमा चौधरी और रवीना टंडन दो बच्चों को जन्म देती है, जिनका नाम टोनी और टुकटुक होता है। दोनों की शक्ल एक जैसी होती है क्योंकि दोनों के पिता गोविंदा ही हैं।

'चिरैया' की सफलता से गदगद हुईं दिव्या दत्ता, सोशल मीडिया पर फैंस का जताया आभार

अभिनेत्री दिव्या दत्ता अपने शानदार अभिनय से दर्शकों में खास पहचान रखती हैं। वे ज्यादातर ऐसे प्रोजेक्ट्स का हिस्सा होती हैं, जो समाज की कुरीतियों और गंभीर मुद्दों पर रोशनी डालती है। इसी कड़ी में वह हाल ही में वेब सीरीज 'चिरैया' में नजर आई थीं। ओटीटी पर स्ट्रीम होने के बाद सीरीज को जबरदस्त प्रतिक्रिया मिल रही है, जिसे देखते हुए अभिनेत्री दिव्या दत्ता ने इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए दर्शकों का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने फिल्म का पोस्टर शेयर कर लिखा, 'हमारे दर्शकों का इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, जिन लोगों को यह सीरीज पसंद आई और जिनसे यह जुड़ गई और जिन्होंने इसे अपना प्यार दिया। उन सभी को तहे दिल से शुक्रिया। 'छह एपिसोड वाली हिंदी ड्रामा वेब सीरीज वैवाहिक दुष्कर्म और पितृसत्तात्मक दबाव के गंभीर विषय पर आधारित है। सीरीज के जरिए निर्देशक शशांत शाह ने उन कुरीतियों पर सोचने पर मजबूर किया है, जो सालों से प्रथा के तौर पर समाज में चली आ रही हैं, जिन पर आजतक किसी ने सवाल नहीं किया।

'चिरैया' की कहानी एक ऐसी महिला के इर्द-गिर्द घूमती है, जो शादी के बाद भी अपने अधिकारों और सहमति के मुद्दे पर आवाज उठाती है। यह सीरीज सीधे-सीधे पूछती है, क्या शादी करने भर से जीवन भर की सहमति मिल जाती है? क्या पति को जबरदस्ती करने का हक है?

शशांत शाह द्वारा निर्देशित सीरीज में दिव्या दत्ता मुख्य भूमिका में हैं, जो कुरीति पर सवाल उठाने के साथ-साथ अपनों से ही लड़ती दिख रही हैं। वहीं, इसमें संजय मिश्रा भी अहम किरदार में हैं। इसके अलावा सिद्धार्थ शॉ, प्रसन्ना बिष्ट, फैसल राशिद, टिन्नू आनंद और सरिता जोशी जैसे कलाकार भी खास भूमिकाओं में हैं। यह सीरीज एसवीएफ एंटरटेनमेंट द्वारा बनाई गई है और जियो हॉटस्टार पर एक्सक्लूसिव तौर पर स्ट्रीम हो रही है।

प्रेरणा की तलाश में

नॉवेल, म्यूजिक व पॉडकास्ट से मिला सुकून

मनोरंजन की दुनिया में अक्सर सितारे अलग-अलग चीजों से प्रेरणा लेते हैं। कुछ ऐसा ही अनुभव बॉलीवुड एक्ट्रेस रसिका दुग्गल ने साझा किया। उन्होंने मंगलवार को इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए फैंस को बताया कि उन्हें पिछले कुछ महीनों में किन-किन चीजों से प्रेरणा मिली है। रसिका दुग्गल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर अपनी एक तस्वीर साझा की, जिसमें वह अपने बालों के साथ खेलती नजर आ रही हैं।इस तस्वीर के साथ उन्होंने एक लंबा कैप्शन लिखा, जिसमें उन्होंने अपनी इंस्पिरेशन सोर्स के बारे में खुलकर बात की। उनकी उपलब्धियां काफी शानदार रही हैं, जिसमें ओलंपिक और वर्ल्ड चैंपियनशिप जैसे बड़े मंचों पर उनकी जीत शामिल है।' रसिका को साहित्य से भी गहरी प्रेरणा मिली। उन्होंने मशहूर लेखिका किरण देसाई के नॉवेल का जिक्र करते हुए कहा, ''उसमें दिखाए गए किरदार सोनिया और सनी के अकेलेपन भरी कहानी ने मेरे दिल को छू लिया। 90 के दशक में भारत में बड़े हुए लोगों के लिए यह कहानी बेहद करीब महसूस होती है। मैडस किताब में इतनी खो गईं कि आज भी इसके बारे में सोचती रहती हूं और कभी-कभी सपनों में भी इसकी झलक देखती हूं। पोस्ट के कैप्शन में रसिका ने आगे लिखा, ''संगीत की बात करें तो मैंने एलिसा लियू की परफॉर्मेंस को बार-बार देखा है, जिसके बाद मेरा झुकाव डिस्कोम्यूजिक की ओर भी बढ़ गया। 'मैकआर्थर पार्क सुइट' अब मेरे पसंदीदा गानों में शामिल हो गया है और मैं इसे बार-बार सुनती हैं। इससे पहले मैं 'छह रही काली घटना' जैसे गाने ज्यादा सुनती थीं, लेकिन अब मेरी पसंद में बदलाव आया है और मैं अपनी मॉर्निंग वॉक के दौरान डिस्को गानों का भी आनंद लेती हैं।''

हमेशा ऐसी चीजें ढूंढती रहती हैं

उन्होंने बताया कि वह हमेशा ऐसी चीजें ढूंढती रहती हैं, जो उनके मन के इमोशन्स को बदल सकें और उन्हें अंदर से मजबूत बना सकें। रसिका ने कैप्शन में लिखा, ''इंस्पिरेशन की तलाश में... हमेशा कुछ ऐसा ढूंढती रहती हूं जो मेरे एहसासों को थोड़ा बदल दे, मेरे मन की बात कह दें... पिछले कुछ महीनों में कुछ चीजें मेरे लिए खास प्रेरणा का स्रोत रही है। इस दौरान रसिका ने खासतौर पर फिगर स्केटर एलिसा लियू का जिक्र किया और लिखा, ''उनकी शानदार वापसी ने मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित किया। एलिसा की वापसी प्रेरणादायक रही। यह एक ऐसी कमबैक कहानी है, जिसमें मेहनत, आत्मविश्वास और अपने तरीके से आगे बढ़ने की ताकत साफ दिखाई देती है।

करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश ने गुपचुप कर ली शादी? वायरल खबरों पर अब खुद तेजा ने दी प्रतिक्रिया

टीवी की दुनिया के पसंदीदा कपल तेजस्वी प्रकाश और करण कुंद्रा की शादी का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। दोनों लंबे वक्त से एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं। फैंस को इंतजार है कि दोनों इस साल शादी के बंधन में बंध जाएंगे। इस बीच हाल ही में ऐसी अफवाहें भी उड़ी थीं कि इस जोड़े ने गुपचुप तरीके से शादी कर ली है। अब तेजस्वी प्रकाश ने इन अफवाहों पर प्रतिक्रिया देते हुए पूरी सच्चाई से

करण कुंद्रा से काफी कुछ सीखने को मिलता है

हालिया बातचीत में तेजस्वी प्रकाश ने करण कुंद्रा के साथ अपनी शादी की योजनाओं के बारे में बात की। एक्ट्रेस ने शादी को लेकर स्पष्ट तौर पर कहा कि ऐसा अभी जल्द ही होने वाला नहीं है। यह कपल 'लाफ्टर शेफ' सीजन 3 में साथ काम कर रहा है। एक-दूसरे के साथ काम करने के बारे में बात करते हुए तेजस्वी ने कहा कि पेशेवर तौर पर एक-दूसरे के साथ काम करते हुए आप कई नई चीजें सीखते हैं। आप एक-दूसरे के काम करने के तरीके को समझने लगते हैं। खासकर मेरे मामले में करण से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि वह मेरे सीनियर हैं। मेरे लिए यह एक सीखने का अनुभव रहा है।

करण ने शादी पर किया था ये रिएक्ट

करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश की शादी को लेकर फैंस लंबे वक्त से कयास लगा रहे हैं। इससे पहले जब तेजस्वी के साथ उनकी गुपचुप शादी की अफवाहें ऑनलाइन फैलीं, तो करण कुंद्रा ने भी इस पर रिएक्ट किया था। उन्होंने मजाकिया अंदाज में एक्स पर लिखा था, 'शादी की तो चलो हर दो चार साल बाद करवा ही देते हैं।'

'गिन्नी वेड्स सनी 2' का 'तुमपे ही प्यार आ गया' गाना रिलीज

अविनाश तिवारी ने बताया, 'धीरे-धीरे दिल में उतरने वाला इश्क'

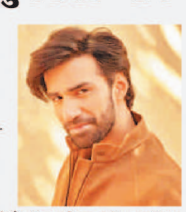

बॉलीवुड में रोमांटिक गानों का अपना एक अलग ही जादू होता है। कुछ गाने ऐसे होते हैं, जो पहली बार में ही दिल को छू लेते हैं। इसी तरह का एक नया रोमांटिक गाना इन दिनों काफी चर्चा में है, जो आने वाली फिल्म 'गिन्नी वेड्स सनी 2' का हिस्सा है। इस गाने का नाम 'तुमपे ही प्यार आ गया' है, जिसे दर्शक काफी पसंद कर रहे हैं। फिल्म में मुख्य किरदार निभा रहे अभिनेता अविनाश तिवारी ने गाने को 'धीरे-धीरे बढ़ने वाला इश्क' करार दिया। उन्होंने कहा, ''यह गाना ऐसा है, जो धीरे-धीरे लोगों को पसंद आएगा। यह कोई तुरंत असर करने वाला गाना नहीं है, बल्कि इसे महसूस करने में थोड़ा समय लगता है। लेकिन एक बार जब यह गाना दिल में बस जाता है, तो फिर इसे भूलना मुश्किल है। उन्होंने कहा, 'गाने की खासियत इसके भाव और कहानी में छिपी है। 'तुमपे ही प्यार आ गया' एक सॉफ्ट और रोमांटिक गाना है, जो दोस्ती से प्यार बनने के सफर को बहुत ही खूबसूरती से दिखाता है।

कवर्धा के राजवीर, वासु और शशांक का 10वीं बोर्ड में उत्कृष्ट परिणाम

नई दृष्टिबिंदु / कवर्धा

सीबीएसई कक्षा 10वीं परीक्षा 2026 में गुरुकुल पब्लिक स्कूल, कवर्धा के विद्यार्थियों ने शानदार प्रदर्शन कर विद्यालय और जिले का नाम रोशन किया है। विद्यालय से कुल 135 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी, जिनमें सभी छात्र-छात्राएं सफल रहे। इनमें से 82 विद्यार्थियों ने प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होकर उत्कृष्ट परिणाम दर्ज किया। परिणामों में राजवीर सिंह राजपूत ने 97% अंक प्राप्त कर विद्यालय में पहला स्थान हासिल किया। वहीं वासु दुबे ने 94.6% के साथ दूसरा और शशांक महोबिया ने 92.2% अंक लेकर तीसरा स्थान प्राप्त किया।

विद्यालय प्रबंधन ने इस उपलब्धि पर खुशी जताते हुए कहा कि यह परिणाम विद्यार्थियों की मेहनत और शिक्षकों के मार्गदर्शन का नतीजा है। प्राचार्य ने सभी सफल विद्यार्थियों और शिक्षकों को बधाई देते हुए भविष्य में और बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद जताई। संस्था के पदाधिकारियों ने भी मेधावी छात्रों को शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की है।

दी होली किंगडम सीनियर सेकेंडरी स्कूल के विद्यार्थियों ने CBSE 10वीं बोर्ड परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन

कवर्धा के दी होली किंगडम सीनियर सेकेंडरी स्कूल के विद्यार्थियों ने उड़रए 10वीं बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए विद्यालय का नाम रोशन किया है। इस वर्ष विद्यालय का परिणाम बेहद प्रभावशाली रहा। प्रज्ञा वंदेल ने 94% अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान हासिल किया, जबकि यथार्थ शर्मा (91%) द्वितीय और रूद्र प्रताप ठाकुर (89%) तृतीय स्थान पर रहे। इसके अलावा रेहान अंसारी (88.4%), विशिष्ट श्रीवास्तव (85.4%), इशिका सिंह (85%), योगेंद्र साहू (83.2%), तनीषा कौशिक (83%), रणवीर सिंह साहू (82.8%) और शौर्य चंद्रवंशी (82.2%) ने भी उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। विद्यालय के कुल 31 विद्यार्थियों ने विशिष्ट श्रेणी प्राप्त की, जो छात्रों की मेहनत और शिक्षकों के मार्गदर्शन को दर्शाता है। विद्यालय के टॉपर प्रज्ञा वंदेल ने अपनी सफलता से न केवल स्कूल बल्कि अपने परिवार का भी नाम रोशन किया। अन्य विद्यार्थियों ने भी बेहतर प्रदर्शन कर सामूहिक सफलता में योगदान दिया। विद्यालय प्रबंधन ने इस उपलब्धि पर हर्ष व्यक्त करते हुए विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों को बधाई दी। संचालक पास्टर जोस थॉमस एवं श्रीमती लिजी थॉमस ने छात्रों को भविष्य में भी इसी तरह उत्कृष्ट प्रदर्शन जारी रखने के लिए प्रेरित किया। प्रबंधन ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और विद्यार्थियों के समग्र विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है।

खास खबर

गुरुकुल में संगीत उत्सव की धूम, नवनिर्मित सभागार का भी हुआ लोकार्पण

नई दृष्टिबिंदु / कवर्धा

कवर्धा के गुरुकुल पब्लिक स्कूल हमेशा अपने सामाजिक सरोकारों एवं भारतीय संस्कृति को ध्यान में रखते हुए विविध कार्यक्रमों का आयोजन करता है, जिससे विद्यालय के विद्यार्थियों के अंतर्निहित प्रतिभा का समुचित विकास हो सके। इसी कड़ी में विद्यालय में संगीत उत्सव समारोह के अंतर्गत अंतर्विद्यालयीन संगीत गायन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता के दो वर्ग थे - कनिष्ठ वर्ग और वरिष्ठ वर्ग। मीडिया प्रभारी ने प्रैस विज्ञप्ति के माध्यम से बताया कि शाला के प्राचार्य के मार्गदर्शन में आयोजित इस कार्यक्रम के अतिथि जिला शिक्षा अधिकारी एफआर वर्मा तथा विशिष्ट अतिथि संदीप अग्रवाल थे। इस अवसर पर विद्यालय प्रबंधन समिति के वरिष्ठ पदाधिकारीगण भी उपस्थित थे।

सर्वप्रथम अतिथियों ने माँ सरस्वती के तैलचित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन- वंदन किया। प्राचार्य ने सभी का आत्मीय स्वागत किया। उन्होंने इस आयोजन के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए कहा कि संगीत आत्मा की भाषा है जो अपनी सरसता से सभी को वशीभूत रखने की शक्ति रखती है। तत्पश्चात गुरुकुल पब्लिक स्कूल, पीएमश्री केंद्रीय विद्यालय महाराजपुर ,अभ्युदय स्कूल ,अशोका पब्लिक स्कूल तथा दिल्ली पब्लिक स्कूल के प्रतिभागियों द्वारा सरस राजस्थानी व सूफी भजन का गायन किया गया।

इस अवसर पर वरिष्ठ तिथियों एवं निर्णायक मंडल के सदस्यों ने भी अपने उद्गार व्यक्त किया। प्रबंधन समिति के वरिष्ठ निदेशक महावीर जैन ने अपने उद्बोधन में कहा कि गुरुकुल विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए सदैव प्रयत्नशील है। विद्यार्थियों के शिक्षणेतर प्रतिभा विकास के लिए यह नवनिर्मित सभागार उन्हें दिया जा रहा है।

सर्वश्रेष्ठ गायन के तौर पर कनिष्ठ वर्ग में प्रथम दिल्ली पब्लिक स्कूल, द्वितीय अभ्युदय स्कूल , तृतीय पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय तथा वरिष्ठ वर्ग में प्रथम अभ्युदय स्कूल द्वितीय पीएमश्री केंद्रीय विद्यालय तथा तृतीय गुरुकुल पब्लिक स्कूल को पुरस्कृत किया गया। इस अवसर पर विद्यालय में नवनिर्मित सर्व सुविधा संपन्न सभागार का भी लोकार्पण किया गया। प्रबंधन समिति के अध्यक्ष तथा अन्य पदाधिकारीगण ने सभी विजेताओं को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की मंगलकामना की।

जनदर्शन में लंबे समय से बंद मार्ग खुला, बुद्धुभरदा में त्वरित कार्रवाई से ग्रामीणों को मिली राहत

राजनांदगांव। कलेक्टर जितेन्द्र यादव के निर्देशानुसार जनदर्शन में प्राप्त आवेदनों पर त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है, जिससे आम नागरिकों को समयबद्ध राहत मिल सके। इसी कड़ी में डोंगरगांव विकासखंड के ग्राम बुद्धुभरदा में निस्तारी मार्ग लंबे समय से बंद होने की शिकायत पर राजस्व विभाग द्वारा तत्परता से कार्रवाई करते हुए मार्ग को बहाल कर दिया गया है। ग्राम बुद्धुभरदा में अनावेदक यशवंत साहू एवं कोमल साहू द्वारा निजी भूमि पर सीमेंट के खंभे एवं तार लगाकर किसानों के निस्तारी मार्ग को लंबे समय से बंद कर दिया गया था, जिससे ग्रामीणों को आवागमन में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था। इस संबंध में ग्रामीणों द्वारा कलेक्टर जनदर्शन में आवेदन प्रस्तुत कर समस्या के निराकरण की मांग की गई थी। जिला प्रशासन के निर्देश पर राजस्व विभाग द्वारा मामले को गंभीरता से लेते हुए त्वरित कार्रवाई की गई। राजस्व अधिकारियों की उपस्थिति में संबंधितों द्वारा सीमेंट के खंभे एवं तार को मेड़ से हटा दिया गया, जिससे निस्तारी मार्ग पुनः सुचारू रूप से चालू हो गया है। मार्ग बहाल होने पर ग्रामवासियों ने जिला प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए राहत की भावना जाहिर की है।

चना, मसूर व सरसों विक्रय के लिए पंजीयन 20 तक, किसान शीघ्र पंजीयन कर लाभ प्राप्त करें

नई दृष्टिबिंदु / राजनांदगांव

कलेक्टर जितेन्द्र यादव द्वारा जिले में रबी मौसम की दलहन एवं तिलहन फसलों का उत्पादन करने वाले किसानों के उत्पाद को प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) अंतर्गत समर्थन मूल्य पर खरीदी सुनिश्चित करने हेतु कृषि विभाग सहित संबंधित विभागों को किसानों का पंजीयन शीघ्र पूर्ण करने तथा समुचित व्यवस्था बनाकर खरीदी करने के निर्देश दिए गए हैं।

निर्देशों के पालन में जिले की 15 प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों एवं एक एफपीओ स्वर्ण उपज महिला किसान उत्पादक कंपनी लिमिटेड सुकुलदैहान द्वारा पीएम-आशा योजना अंतर्गत दलहन एवं तिलहन फसलों की खरीदी की जा रही है। भारत सरकार द्वारा किसानों के हित में तथा दलहन एवं तिलहन क्षेत्र के विस्तार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) अंतर्गत प्राइस सपोर्ट स्कीम (पीएसएस) लागू की गई है। जिले में 15 उपार्जन केन्द्रों एवं एक एफपीओ को अधिसूचित किया गया है। राज्य शासन द्वारा नाफेड के माध्यम से खरीदी की जा रही है। निर्धारित समर्थन मूल्य के अनुसार सोयाबीन 5328 रूपए प्रति क्विंटल, अरहर 8000 रूपए प्रति क्विंटल, चना 5875 रूपए प्रति क्विंटल, मसूर 7000 रूपए प्रति क्विंटल एवं सरसों 6200 रूपए प्रति क्विंटल निर्धारित है।

उप संचालक कृषि टीकम सिंह ठाकुर ने बताया कि जिले में अब तक कुल 1451 क्विंटल फसलों की सफलतापूर्वक खरीदी की जा चुकी है। जिसमें चना 967.5 क्विंटल, मसूर 374.5 क्विंटल, सरसों 15.5 क्विंटल, अरहर 9 क्विंटल एवं सोयाबीन 73.5 क्विंटल शामिल हैं।

जिले में अब तक 108 कृषकों को कुल 4014733 रूपए की राशि का भुगतान किया जा चुका है। एकीकृत किसान पोर्टल में पंजीयन की स्थिति के अनुसार चना हेतु 3382 किसान, मसूर हेतु 1237 किसान एवं राई व सरसों हेतु 465 किसान, इस प्रकार कुल 5084 किसानों द्वारा पंजीयन कराया जा चुका है। पंजीयन के दौरान यदि रकबा गिरदावरी में प्रदर्शित नहीं हो रहा है, तो संबंधित ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी एवं पटवारी से संयुक्त सत्यापन कर प्रमाण पत्र प्राप्त कर सहकारी समितियों में जमा कर उपार्जन कराया जा सकता है। पंजीयन एवं खरीदी प्रक्रिया अत्यंत सरल है। किसानों को पंजीयन के लिए केवल अपने नजदीकी चिन्हांकित सेवा सहकारी समिति में भूमि एवं फसल संबंधी दस्तावेज, आधार कार्ड एवं बैंक खाता नंबर लेकर पहुंचना है। उपार्जन हेतु राज्य एजेंसी नाफेड के गुणवत्ता सर्वेयर द्वारा मौके पर ही बीजों का परीक्षण कर खरीदी की जा रही है। साथ ही पीएम-आशा योजना अंतर्गत किसानों को एक सप्ताह के भीतर भुगतान सुनिश्चित किया गया है।

पीएम आशा योजनांतर्गत तुमड़ीबोड़ उपार्जन केन्द्र में सफलतापूर्वक सोयाबीन एवं चना विक्रय करने वाले कृषक कमलनारायण साहू ने बताया कि उनके द्वारा खरीफ में 29 क्विंटल सोयाबीन का विक्रय किया गया था। जिसका 186480 रूपए किसान को सीधे उनके खाते में 15 दिवस के अंदर भुगतान हो गया था और उनके द्वारा रबी में 59 क्विंटल चना का विक्रय किया गया है। मंडी मूल्य की तुलना में किसानों को अधिक लाभ मिल रहा है।

वर्तमान में चना का अधिकतम मंडी मूल्य 5070 रूपए प्रति क्विंटल, मसूर 5650 रूपए प्रति क्विंटल तथा सरसों 5662 रूपए प्रति क्विंटल है, जबकि पीएम-आशा योजना अंतर्गत चना 5875 रूपए प्रति क्विंटल, मसूर 7000 रूपए प्रति क्विंटल एवं सरसों 6500 रूपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदी की जा रही है। इससे किसानों को अपनी उपज का बेहतर मूल्य प्राप्त हो रहा है। प्राइस सपोर्ट स्कीम (पीएसएस) अंतर्गत एकीकृत किसान पोर्टल एवं नाफेड के ई-समृद्धि पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन पंजीयन कराएं तथा योजना का लाभ उठाएं। यह योजना किसानों की आय वृद्धि एवं दलहन-तिलहन क्षेत्र विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। चना, मसूर एवं सरसों विक्रय हेतु पंजीयन की अंतिम तिथि 20 अप्रैल 2026 निर्धारित है। कृषक शीघ्र पंजीयन कर योजना का लाभ प्राप्त करें।

कलेक्टर ने महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को कृत्रिम बेबी का किया गया वितरण

नई दृष्टिबिंदु / राजनांदगांव

कलेक्टर जितेन्द्र यादव द्वारा आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में शिशुवती माताओं को स्तनपान के सही तरीके और उसके लाभ की जानकारी देने तथा शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के लिए महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को कृत्रिम बेबी वितरण किया गया।

जिले में स्वास्थ्य क्षेत्र में जागरूकता फैलाने के लिए शिशुवती माताओं में स्तनपान को बढ़ावा देने शिशु मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य से कृत्रिम शिशु मानव आकृति के माध्यम से विशेष जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत उप स्वास्थ्य केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, आंगनबाड़ी केन्द्रों एवं सामुदायिक स्थलों पर एक कृत्रिम शिशु मानव आकृति (कृत्रिम बेबी) की सहायता से माताओं को स्तनपान के सही तकनीकों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ सुश्री सुरूचि सिंह, अपर कलेक्टर सीएल मारकण्डेय, अपर कलेक्टर प्रेम प्रकाश शर्मा, नगर निगम आयुक्त अतुल विश्वकर्मा सहित अन्य जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. नेतराम नवरतन ने बताया कि छः महीने तक केवल मां का दूध देना शिशु के समुचित विकास एवं रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसी उद्देश्य से माताओं को न केवल स्तनपान के महत्व के बारे में बताया जा रहा है। साथ ही कंगारू मदर केयर, प्रमुख स्तनपान पोजीशन जैसे- कैडल होल्ड, क्रॉस-कैडल, फुटबॉल होल्ड, पोजीशन के बारे में भी जानकारी दी जा रही है। उन्होंने बताया कि स्तनपान से शिशु को पर्याप्त एवं संतुलित पोषण मिलता है। शिशु का शारीरिक एवं मानसिक विकास बेहतर होता है।

मां को स्तन संबंधी समस्याओं में राहत मिलती है। शिशु मृत्यु दर में कमी आती है। स्तनपान के दौरान लगाव यानी शिशु द्वारा स्तन को सही तरीके से पकड़ना बहुत जरूरी होता है। साथ ही हाथ को स्तनपान पश्चात बच्चों को डकार दिलाना आवश्यक है। इसे पहचानने के कुछ स्पष्ट संकेत होते है। शिशु का मुंह चौड़ा खुला होता है। शिशु केवल निप्पल नहीं, बल्कि (निप्पल के आसपास का गहरा हिस्सा) भी मुंह मे लेता है। शिशु की ठुड्डी स्तन से लगी होती है। शिशु के होंठ बाहर की ओर मुड़े होते है। दूध पीते समय धीमी और गहरी चूसने की आवाज आती है। इस के साथ ही केवल निप्पल ही मुंह में होना, मां को तेज दर्द या घाव महसूस होना, शिशु का बार-बार स्तन छोड़ देना, दूध कम निकलना या शिशु का असंतुष्ट रहना, चूसने की आवाज स्मैकिंग जैसी होना गलत स्तनपान के संकेत है। एक कृत्रिम शिशु मानव आकृति के माध्यम से इन सभी पोजीशनों का व्यावहारिक प्रदर्शन कर माताओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जिससे वे इन्हे आसानी से समझकर अपनाएं। यह अभियान एक स्वस्थ और सशक्त समाज के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

सुशासन तिहार : की सभी आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करें : कलेक्टर

नई दृष्टिबिंदु / राजनांदगांव

कलेक्टर जितेन्द्र यादव ने आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में साप्ताहिक समय सीमा की बैठक ली। कलेक्टर ने कहा कि जिले में 1 मई से सुशासन तिहार 2026 की शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि शासन द्वारा जन शिकायतों के समयबद्ध एवं प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सुशासन तिहार का आयोजन किया जा रहा है। जिले में 1 मई से 10 जून 2026 तक जनसमस्या निवारण शिविरों का आयोजन किया जाएगा।

उन्होंने सभी अधिकारियों को इसकी आवश्यक तैयारी करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने सख्ती जिले के ग्राम सिंघीतराई में पावर प्लांट में हुए हादसे के मद्देनजर सभी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व और तहसीलदारों को सुरक्षा संबंधी मापदण्डों की जांच करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिले के सभी औद्योगिक प्रतिष्ठानों में ऐसे हादसों से बचाव के लिए सावधानी एवं सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना शासन की महत्वपूर्ण योजना है। जिससे हरित ऊर्जा की ओर लोगों का रूझान बढ़ेगा। इस योजना के अंतर्गत कालोनी में भी सोलर पैनल लगवाने के लिए जनमानस को प्रोत्साहित करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना से अधिक से अधिक लोगों को लाभान्वित करें। कलेक्टर ने कहा कि मिशन जल रक्षा के तहत कृषकों को धान के बदले अन्य फसल लगाने के लिए प्रोत्साहित करें और रबी सीजन में किसानों को धान के बदले अन्य फसल लेने से जल संरक्षण को बढ़ावा मिले। कलेक्टर ने कहा कि कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से सुरक्षा के लिए किशोरी बालिकाओं को एचपीवी वैक्सीन लगाने के लिए जागरूक करें। उन्होंने अधिक से अधिक किशोरी बालिकाओं का टीकाकरण सुनिश्चित करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि ग्रीष्मकाल को ध्यान में रखते हुए पेयजल की समस्या का प्राथमिकता से निराकरण करना सुनिश्चित करें। उन्होंने शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की व्यवस्था की समीक्षा की।

कलेक्टर ने खाद्य सुरक्षा विभाग को खाद्य प्रतिष्ठानों में खाद्य पदार्थों की नियमित जांच करने तथा खाद्य पदार्थ अमानक पाए जाने पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने राजस्व प्रकरणों का गुणवत्तापूर्ण निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने सीमांकन के कार्य में गति लाने के निर्देश दिए। शिविर लगाकर बटवारा, नामांतरण एवं अन्य राजस्व प्रकरणों का तत्परता एवं सक्रियतापूर्वक निराकरण करने के लिए कहा। कलेक्टर ने कहा कि अटल पोर्टल मानिटरिंग में निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप सभी विभाग उत्कृष्ट प्रदर्शन करें तथा समय पर डाटा एण्ट्री करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि ई-ऑफिस के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सभी विभाग ई-ऑफिस के माध्यम से कार्य करेंगें तथा सभी जनपदों में भी ई-ऑफिस के माध्यम से कार्य किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि शहर में नाले की साफ-सफाई निरंतर होनी चाहिए तथा स्वच्छता पर विशेष ध्यान देते हुए कार्य करें। उन्होंने नगर निगम द्वारा किए जा रहे कर संग्रहण के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने जनमानस को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने तथा नियमित योग कराने आयुष विभाग को निर्देश दिए। कलेक्टर ने समर कैम्प, ग्राम पंचायतों में कर वसूली, लोक निर्माण विभाग द्वारा किए जा रहे कार्य, जनदर्शन के प्रकरणों का निराकरण के संबंध में जानकारी ली। जिला पंचायत सीईओ सुश्री सुरूचि सिंह ने कहा कि किशोरी बालिकाओं को कैंसर से बचाव के लिए एचपीवी वैक्सीनेशन तथा नियमया नव्या कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए कहा। इस अवसर पर बैठक में अपर कलेक्टर सीएल मारकण्डेय, अपर कलेक्टर प्रेम प्रकाश शर्मा, नगर निगम आयुक्त अतुल विश्वकर्मा सहित अन्य जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।

कलेक्टर ने औद्योगिक इकाइयों को निर्धारित सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन करने के दिए निर्देश

जिले के विभिन्न औद्योगिक इकाइयों में सुरक्षा मानकों की गई जांच

नई दृष्टिबिंदु / राजनांदगांव

कलेक्टर जितेन्द्र यादव ने सख्ती जिले के ग्राम सिंघीतराई स्थित पावर प्लांट में हुए हादसे को गंभीरता से लेते हुए जिले के सभी औद्योगिक प्रतिष्ठानों में सुरक्षा मानकों की सख्त जांच के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सभी इकाइयों में पर्याप्त सुरक्षा एवं सावधानी अनिवार्य रूप से सुनिश्चित की जाए तथा लापरवाही पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर ने सभी औद्योगिक इकाइयों को निर्देशित किया है कि वे निर्धारित सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन करें तथा श्रमिकों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दें।

कलेक्टर के निर्देशानुसार राजस्व एवं उद्योग विभाग के अधिकारियों द्वारा जिले की विभिन्न औद्योगिक इकाइयों का जांच किया गया। निरीक्षण के दौरान कांकरिया राइस मिल्स दीवानभेड़ी, श्याम इंडस्ट्री महाराजपुर, जनता इंडस्ट्रीज एवं राइस मिल, वधमान राइस मिल जनकपुर, काकरिया पॉलिमर्स पार्रीकला, श्री राम सीमलेस प्राइवेट लिमिटेड पाइप इंडस्ट्री, सुरेश राइस मिल पार्रीकला, जिन्दत्त फूड प्रोसेसिंग यूनिट जनकपुर तथा बालाजी राइस मिल महाराजपुर का जांच किया गया।

जांच के दौरान कांकरिया राइस मिल्स दीवानभेड़ी में फायर सेफ्टी व्यवस्था बढ़ाने के निर्देश दिए गए। श्री श्याम इंडस्ट्री महाराजपुर में केवल एक

अग्निशामक यंत्र पाया गया तथा फायर अलार्म की अनुपस्थिति पर तत्काल अतिरिक्त अग्निशामक यंत्र, फायर अलार्म एवं बालू-पानी की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया। जनता इंडस्ट्रीज एवं राइस मिल में अग्निशामक यंत्र खराब पाए जाने पर एक सप्ताह के भीतर सभी सुरक्षा व्यवस्थाएं दुरूस्त करने के निर्देश दिए गए। वधमान राइस मिल जनकपुर में पर्याप्त अग्निशामक यंत्र उपलब्ध होने के बावजूद फायर अलार्म एवं आपातकालीन नंबर प्रदर्शित नहीं पाए गए, जिन्हें तत्काल स्थापित करने के निर्देश दिए गए।

काकरिया पॉलिमर्स पार्रीकला में एक अग्निशामक यंत्र एक्सपायर पाया गया, जिसे तुरंत रिफिल करने कहा गया। सुरेश राइस मिल पार्रीकला में एक अग्निशामक यंत्र वर्ष 2019 से एक्सपायर पाया गया तथा बायलर निरीक्षण से संबंधित दस्तावेज उपलब्ध नहीं थे, जिस पर तत्काल सुधार के निर्देश दिए गए। जिन्दत्त फूड प्रोसेसिंग यूनिट जनकपुर में फायर अलार्म, बालू-पानी की व्यवस्था एवं आपातकालीन नंबरों का अभाव पाया गया। बालाजी राइस मिल महाराजपुर में भी आंशिक सुरक्षा व्यवस्थाएं पाई गई, जिन्हें शीघ्र पूर्ण करने कहा गया।

क्रेस्ट स्टील एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड के तीनों यूनिट में फायर सेफ्टी सहित अन्य सुरक्षा व्यवस्थाएं पाई गई। यहां नियमित रूप से लॉग बुक संधारित की जा रही है तथा समय-समय पर फायर मॉक ड्रिल एवं सुरक्षा अभ्यास आयोजित किए जा रहे हैं। श्री राम सीमलेस प्राइवेट लिमिटेड पाइप इंडस्ट्री में भी सुरक्षा मानकों का पालन पाया गया।

भीषण गर्मी में सड़कों में बहा लाखों लीटर फिल्टर पानी

नई दृष्टिबिंदु / भिलाई

भिलाई नगर निगम के वार्ड क्रमांक-17 हार्डवेयर लाइन में शुक्रवार की सुबह से ही पाइप लाइन लीकेज होने के कारण पानी लगातार बह रहा है। जानकारी के अनुसार पाइप लाइन गलत फीटिंग होने की वजह से यह छठवीं बार लीकेज हुआ है। पाइप लाइन बार-बार लीकेज होने से भीषण गर्मी में लाखों लीटर फिल्टर पानी सड़कों बह जा रहा है। पाइप लाइन फीटिंग जैसे काम की मॉनिटरिंग पीएचई के इंजीनियर से कराना चाहिए। लेकिन एजेंसी काम निपटाने के चक्कर में आनन-फानन तरीके से करोड़ों का भुगतान पाने काम निपटा कर चली गई है।

संस्कार स्कूल का 10वीं में उत्कृष्ट परिणाम, 99.5 प्रतिशत विद्यार्थियों ने पाई सफलता

नई दृष्टिबिंदु / रायगढ़

जिले की प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्था संस्कार पब्लिक स्कूल ने कक्षा 10वीं के परिणाम में अपना परचम फिर से लहराया है। संस्था के मार्गदर्शक रामचंद्र शर्मा ने बताया कि सीबीएसई द्वारा जारी कक्षा 10वीं के परीक्षा परिणाम में 10 से ज्यादा बच्चों ने 90 प्रतिशत से अधिक प्राप्तांक प्राप्त किए हैं। जबकि 90 प्रतिशत से अधिक विद्यार्थियों ने प्रथम श्रेणी से अधिक अंक प्राप्त करने में सफलता पाई है।

ज्ञात हो कि संस्कार पब्लिक स्कूल लगातार सफलता के सोपान तय कर रहा है। जिसमें व्यक्तित्व विकास संबंधी गतिविधियों के साथ-साथ अकादमिक क्षेत्र में भी अपने झंडे गाड़ रहा है। प्राप्त रिजल्ट में टॉपर बच्चों में दिशांत पटेल, निधि पंकज, प्रिया पैंकरा, अन्वेष प्रधान, साक्षी रुपेता, अभिराज शर्मा, अग्रिमा दुबे, अभिनव कुमार, तमन्ना प्रधान, विख्यात गुप्ता, नाजनीन परवीन, श्रेया पटेल, दिव्या बिश्नोई, मेघा साहू, पीयूष मरावी, साहिल यादव, वीणा रात्रे, सम्राट मित्तल, जिज्ञासा खांडे, सूरज बरनवाल, मितांली मालाकार, यश नायक, शशांक मणि, प्रिया शर्मा, ईशान पांडेय आदि शामिल हैं।

संस्था की प्राचार्य रश्मि शर्मा, एक्टिंग डायरेक्टर सीपी देवांगन सहित संपूर्ण स्टाफ ने बच्चों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं।

विधायक देवेंद्र यादव ने की जनता से भेंट मुलाकात, कलेक्टर से चर्चा कर जल्द निराकरण की कही बात

नई दृष्टिबिंदु / भिलाई

सेक्टर-5 स्थित विधायक देवेंद्र यादव कार्यालय में रोज की तरह आज भी भेंट-मुलाकात के लिए उपस्थित रहे , जिसमें भिलाई के विभिन्न क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे। विधायक ने एक-एक कर सभी की बात सुनी और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।

इस दौरान सेक्टर-3 एवं वार्ड-43 बापूनगर के रहवासियों ने गंदे पानी की गंभीर समस्या से अवगत कराया। स्थानीय नागरिकों ने बताया कि लंबे समय से दूषित पानी की आपूर्ति हो रही है, जिससे लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। समस्या की गंभीरता को देखते हुए विधायक ने तत्काल जिला कलेक्टर से फोन पर चर्चा कर शीघ्र समाधान के निर्देश दिलवाए। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट रूप से कहा कि पेयजल जैसी बुनियादी सुविधा में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

भेंट-मुलाकात कार्यक्रम में निगम क्षेत्र, ग्रामीण इलाकों सहित विभिन्न वार्डों से आए लोगों ने सड़क, बिजली, पानी, सफाई, आवास सहित अन्य समस्याएं रखीं। विधायक ने सभी मामलों को गंभीरता से लेते हुए संबंधित विभागों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए और आश्वासन दिया कि जनता की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा।

कार्यक्रम के बाद विधायक बापूनगर स्थित गुरुद्वारा पहुंचे, जहां प्रकाश पर्व के अवसर पर आयोजित धार्मिक कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने गुरुद्वारे में मत्था टेककर प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि की कामना की तथा संगत के साथ समय बिताया। इस अवसर पर उन्होंने सामाजिक सौहार्द और आपसी भाईचारे को मजबूत बनाने का संदेश भी दिया। विधायक देवेंद्र यादव ने कहा कि वे निरंतर जनता के बीच रहकर उनकी समस्याओं के समाधान के लिए प्रतिबद्ध हैं और भिलाई के समग्र विकास के लिए हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं।

लू को लेकर मौसम विभाग ने जताई संभावना

रायपुर। अप्रैल का आधा महीना निकल चुका है, तो वहीं दूसरी ओर भीषण गर्मी ने लोगों को बेहाल कर दिया। महीने के पहले ही हफ्ते से तापमान तेजी से बढ़ गया है, जिससे लोगों का हाल बेहाल हो गया है। दोपहर के समय लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। बात करें छत्तीसगढ़ की तो यहां मौसम में गर्मी ने पूरी तरह आक्रामक रुख अपना लिया है। तापमान 41 डिग्री के पार पहुंचते ही प्रदेश के कई इलाके हीट जोन में बदलने लगे हैं। जिले की बात करें तो सबसे ज्यादा राजनांदगांव और धमतरी में तापमान दर्ज किया गया है, यहां 43.5 डिग्री तापमान तक पहुंच गया। वहीं राजधानी रायपुर में 43 डिग्री और बिलासपुर में 42.8 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। इसके अलावा जगदलपुर में 40 तो अंबिकापुर में 39.3 डिग्री तापमान दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले तीन दिनों में तापमान में 1 से 3 डिग्री तक और बढ़ोतरी हो सकती है। इतना ही नहीं, 17 से 19 अप्रैल के बीच बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग संभाग में लू चलने की भी संभावना जताई गई है।

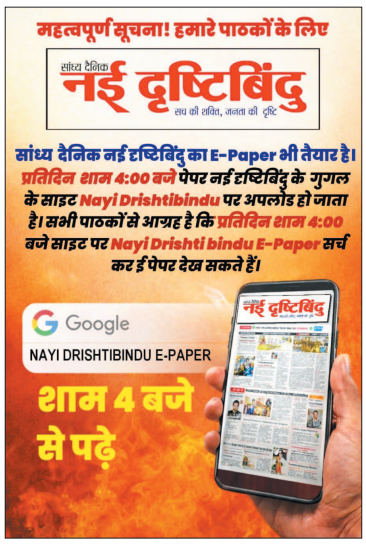

"यह समाचार पत्र आलोक तिवारी द्वारा 80/बी, मैत्री विहार, राधिका नगर, सुपेला, भिलाई, जिला दुर्ग, (छत्तीसगढ़)-490023 से आलोक तिवारी की ओर से प्रकाशित की जाती है, जिसका संपादन आलोक तिवारी द्वारा किया जाता है तथा इसका मुद्रण समय दर्शन प्रिंटर्स एंड पब्लिशर्स द्वारा प्लॉट नं. 339/6, गली नं. 02, पाटन, थाना उतई, दुर्ग, (छ.ग.)-491111 पर किया जाता है। (समाचार चयन के लिए PRP Act, 2023 के तहत संपादक जिम्मेदार है)। समस्त विवादों का निपटारा न्यायालयीन क्षेत्र दुर्ग होगा।" संपादक आलोक तिवारी, मो. 74154-69100